आज का विचार

जिनके स्वभाव में प्रेम बना हुआ है। उनके दरवाजे पर खुशियां खुद चलकर आती हैं।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ | बुधवार, 18 मार्च, 2026 | वर्ष 24, अंक 67, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 | www.citydarpan.com

यदि भगत सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का नक्शा कुछ और होताः भगवंत सिंह मान

कहा- आजादी के इतने सालों बाद भी हम पुराने सिस्टम के गुलाम हैं, क्या भगत सिंह और करतार सिंह सराभा इसी वजह से शहीद हुए थे?

यज्ञांश शर्मा

चंडीगढ़/धूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि यदि शहीद-ए-आजम भगत सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो आज देश का नक्शा बिल्कुल अलग होता। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आजादी के दशकों बाद भी देश पुराने सिस्टम के जाल में क्यों उलझा हुआ है, जबकि इसी सिस्टम से मुक्ति के लिए भगत सिंह और करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्योछावर की थी। उन्होंने कहा कि यह दीवार पर लिखी बात पढ़ लेनी चाहिए कि वर्ष 2027 में भी आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आएगी, क्योंकि चार वर्षों में सभी गारंटियां पूरी कर दी गई हैं और विरोधियों के पास जनता के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियां बारी-बारी से पंजाब को लूटने के बाद अब फिर सत्ता में आने के लिए आपस में लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों को पंजाब अभी तक नहीं भूला है।

आज नए बने सब-डिवीजनल अस्पताल को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, यह दीवार पर लिखी बात पढ़ लेनी चाहिए कि जनहित में लिए गए फैसलों के कारण आप राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा, पंजाब के लोग 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद आप की सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं। वर्ष 2022 में शहीद-ए-आजम

भगत सिंह के पैतृक गांव से सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने कई जनहितकारी फैसले लिए। हमने चार वर्षों में अपने सभी वादे पहले ही पूरे कर लिए हैं और आने वाले एक वर्ष में हम राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। शासन व्यवस्था में नई पहल का उल्लेख करते हुए मान ने कहा, हमने चार साल में सभी वादे पूरे कर राजनीति में एक नई परंपरा शुरू की है, जबकि अन्य पार्टियां पांच साल में भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले दिन से ही हमारी सरकार पिछली सरकारों के खराब सिस्टम को सुधार रही है और हम आम आदमी की भलाई के लिए साहसिक फैसले लेने से नहीं हिचकते। उन्होंने आगे कहा, अब कांग्रेस और बादल फिर से राज्य को लूटने का एक और मौका तलाश रहे हैं, जबकि राज्य पहले ही इनके शासनकाल में बहुत कुछ झेल चुका है। लोगों की भावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, राज्य के समझदार लोग इन्हें कभी भी एक और मौका नहीं देंगे और चुनावों के बाद इन्हें राजनीतिक गुमनामी में भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, जिन नेताओं ने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया था, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। इन नेताओं ने न केवल राज्य में नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि अपनी सरकारी गाड़ियों में नशे बेचे और सप्लाई भी किए। पहले किसी ने भी इन प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा किया और अब वे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इन नेताओं की आपसी मिलीभगत का जिक्र करते हुए मान ने कहा, इन राजनीतिक पार्टियों के बीच एक नापाक गठजोड़ बना हुआ था क्योंकि वे राज्य का खजाना लूटने के लिए एक-दूसरे से हाथ मिला लेते थे। जब ये सत्ता में होते थे तो एक-दूसरे के अपराधों को छुपाने के लिए जानबूझकर आंखें मूंद लेते थे और बचाव कर लेते थे। हालांकि, आप सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस घिनौने अपराध के दोषियों को जेल भेजा जाए।

बच्चों को पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना जरूरीः द्रोपदी मूर्मू

स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अभिभावकों के लिए बच्चों को स्कूल भेजने का एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन साबित हुआ

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि देश के भविष्य हमारे बच्चे हैं और उन्हें पौष्टिक भोजन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रपति मुर्मु ने मंगलवार को अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा पांच अरब भोजन परोसने की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। पीएम पोषण के तहत चल रहा स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अभिभावकों के लिए बच्चों को स्कूल भेजने का एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन साबित हुआ है। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना से बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और स्कूल में टिके रहने की दर में वृद्धि हुई है, साथ ही उनकी सीखने की क्षमता और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है।

राष्ट्रपति ने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने पांच अरब भोजन उपलब्ध कराने की उपलब्धि को सराहनीय बताते हुए कहा कि कार्यक्रम की थीम पोषित और शिक्षित भारत से विकसित भारत हमारे राष्ट्रीय संकल्प विकसित भारत 2047 को साकार करने में पोषण और शिक्षा की अहम भूमिका को दशार्ती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों की साझा जिम्मेदारी है। जब शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक संगठन, कॉरपोरेट क्षेत्र और समाज के सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत नींव तैयार होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में अवसरों का निर्धारण करती है और उसे सशक्त बनाती है। स्कूल बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव प्रदान करता है।

राष्ट्रपति ने पिछले 25 वर्षों से बच्चों में कुपोषण दूर करने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के कार्य में जुटे अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चे केवल इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य के निमार्ता हैं। आज उन्हें मिलने वाला पौष्टिक भोजन देश की मानव पूंजी में निवेश है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना का सार

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्कॉन के संस्थापक-आचार्य श्रील प्रभुपाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से यह निःस्वार्थ खाद्य वितरण पहल शुरू हुई और आज एक जनआंदोलन का रूप ले चुकी है। 25 वर्षों की यह यात्रा आसान नहीं रही। आज इस जनआंदोलन के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक भारत का शिक्षा क्षेत्र है। 16 राज्यों और 25 हजार से अधिक स्कूलों में आप प्रतिदिन 23.5 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे बच्चे और युवा सुपोषित नहीं होंगे, तब तक भारत अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं कर सकता। आज भारत का विकास केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक दक्षिण और मानवता के कल्याण के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। यही वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना का सार है। अक्षय पात्र फाउंडेशन पीएम पोषण योजना के एक महत्वपूर्ण कार्यान्वयन भागीदार के रूप में उभरा है। गुणवत्ता, स्वच्छता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से इसने इस मिशन को और सशक्त बनाया है। यह साझेदारी इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि सरकार, समाज और संस्थाएं मिलकर देश की जटिल चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकती हैं। देश के हर बच्चे तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना केवल सेवा नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति हमारा संकल्प है। यह देश के युवाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का हर बच्चा सुपोषित होगा और हर बच्चा स्कूल में बना रहेगा। अक्षय पात्र के संस्थापक-चेयरमैन और इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष मधु पंडित दास ने कहा कि जब हम मानवता की सेवा के 25 वर्ष और 5 अरब भोजन परोसने की उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, तब हम श्रील प्रभुपाद के उस महान संकल्प को दोहराते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।

लोकसभा में विपक्ष के 8 सदस्यों का निलंबन वापस लिया गया

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

लोकसभा ने मंगलवार को विपक्ष के आठ सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया, जिसका ध्वनिमत से सभी ने एकमत होकर समर्थन किया। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण में 3 फरवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने देने के खिलाफ विपक्षी सदस्यों ने आसन के सामने आकर भारी विरोध प्रदर्शन किया था। उस संदर्भ में सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और हंगामा करने के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित किया गया था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सोमवार को सभी दलों के नेताओं संग हुई बैठक में इस मुद्दे को लेकर पक्ष-विपक्ष में चल रही तनातनी का हल निकालने के लिए इन सदस्यों का निलंबन खत्म करने पर यह सहमति बनी थी। इन सदस्यों में सर्वश्री गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. प्रशांत यादवराव पाडोले, चामला किरण कुमार रेड्डी और एस. वेंकटेशन थे। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सदन में प्रस्ताव पेश करने के दौरान कहा कि सदन के प्रभावी और फलदायी संचालन के लिए सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। सदन में नियम कार्य-प्रक्रिया की परंपरा हैं। कल हमने कहा था कि यदि विपक्ष सदन और अध्यक्ष के नियमों का पालन करने में हमारी मदद करता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। यदि विपक्ष सीमाओं के निर्धारण पर सहमत होता है और प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, तो हम भी उसका पालन कर सकते हैं। इसके बाद रिजिजू ने 8 निलंबित सांसदों के निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के मुताबिक पिछली बैठक में यह भी सहमति बनी कि संसद की गरिमा और स्थापित परंपराओं का सभी द्वारा पालन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया कि कोई भी सदस्य वेल में दूसरी तरफ नहीं जाएगा, कागज फाड़कर आसन की ओर नहीं फेंकेगा और अधिकारियों की मेज पर नहीं चढ़ेगा। इसके अलावा, सभी सदस्य सदन की मयार्दा का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएँ भविष्य में दोबारा न हों। इस बीच, लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को संसद परिसर में मयार्दा बनाए रखने के संबंध में एक बुलेटिन जारी किया है। इसमें दिशा-निर्देश 124ए(2) का हवाला दिया गया है, जो संसद परिसर के क्षेत्र और मार्ग को सांसदों के लिए खुला और बाधारहित बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाता है। बुलेटिन में विशेष रूप से कहा गया है कि परिसर में हथियार, झंडे, पोस्टर, लाठी, भाला, तलवार, डंडे और ईंट आदि ले जाना निषिद्ध है। सांसदों को बार-बार निर्देश दिया गया है कि वे पोस्टर, प्लैकार्ड या बैनर न लाएँ और न प्रदर्शित करें। इसके अलावा, बुलेटिन में कहा गया है कि कुछ मामलों में पोस्टर और प्लैकार्ड पर एआई-जनित आपत्तिजनक चित्र, तस्वीरें और नारे प्रदर्शित किए गए हैं। सांसदों को एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देश का कड़ाई से पालन करें, ताकि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ने आज सदन में कहा सभी से आग्रह किया कि संसद परिसर में, सदन के अंदर या बाहर, फर्जी तस्वीरें, एआई-जनरेटेड तस्वीरें, पोस्टर या बैनर प्रदर्शित न करें।

तंबाकू की जगह वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने पर काम कर रही सरकारः कृषि मंत्री

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि तंबाकू सेवन के विभिन्न तरीकों के कारण देश में हर साल करीब 13 लाख लोगों की मौत होती है। इसके कारण सरकार तंबाकू की खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।

कृषि मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान घोषी से समाजवादी पार्टी के सदस्य राजीव राय के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि सरकार ने किसानों से तंबाकू की खेती छोड़ने के लिए नहीं कहा है, बल्कि उनके लिए विकल्प तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि किन-किन इलाकों में तंबाकू की जगह कौन-कौन सी फसलें पैदा की जा सकती हैं, इसका भी अध्ययन किया गया है। इनमें हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, आलू, चिया, फीडबीन, लोबिया, रागी, मूंगफली, सोयाबीन और ज्वार जैसी फसलें शामिल हैं।

शिवराज ने कहा कि छोटे किसानों के लिए एकीकृत खेती मॉडल पर काम किया जा रहा है। छोटे किसान केवल एक फसल पर निर्भर न रहें, बल्कि चावल, सब्जियां, दलहन, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे विविध क्षेत्रों में ध्यान दें। इसके लिए कई जगहों पर डेमोंस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं ताकि छोटे किसानों की खेती लाभकारी व्यवसाय बन सके।

हरियाणा में राज्य सभा की एक सीट भाजपा व एक कांग्रेस को मिली

एजेंसी (हि.स.)

चंडीगढ़

हरियाणा में राज्य सभा की दो सीटों पर हुए मतदान के बाद मंगलवार तड़के करीब पौने तीन बजे घोषित परिणाम के अनुसार एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया तथा दूसरी सीट पर कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध निर्वाचित हुए हैं। सोमवार को दिनभर नाटकीय घटनाक्रम में हुए मतदान के बाद करीब 11 घंटे तक मतगणना पर घमासान चलता रहा।

सोमवार शाम चार बजे तक हुए मतदान के दौरान कुल 90 में से 88 विधायकों ने वोट डाला। इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायको अर्जुन

चौटाला व आदित्य देवीलाल ने मतदान नहीं किया। विधायकों की संख्या के अनुसार भाजपा के संजय भाटिया का पहले ही चुना जाना तय था। सोमवार शाम पांच बजे मतगणना शुरू होने से पहले भाजपा ने टोहाना के विधायक परमवीर सिंह तथा ऐलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल की वोट पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत की। वहीं, कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज की वोट पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। विवाद बढ़ने पर रात करीब साढे नौ बजे कांग्रेस का एक शिष्टमंडल केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई।

रात करीब 11.30 बजे कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह की वोट को रद्द कर दिया गया और भरत सिंह बेनीवाल तथा अनिल विज की वोट को मान्य करार दिया गया। इसके बाद मतगणना के आदेश जारी हुए।

विपक्ष कर्ज के गलत आंकड़े देकर जनता को कर रहा गुमराहः नायब सिंह सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष ने आशंका व्यक्त की है कि यदि कर्ज बढ़ता रहा तो हरियाणा भी पंजाब की तरह आर्थिक संकट में फंस सकता है और आने वाली पीढ़ियों को इसका 'डिफर्ड बर्डन' झेलना पड़ेगा। विपक्ष की यह आशंका वास्तविकता से बहुत परे है। विपक्ष कर्ज के गलत आंकड़े देकर जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल भावनात्मक टिप्पणियों से नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। हरियाणा की वित्तीय स्थिति को यदि पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ तुलनात्मक रूप से देखा जाए, तो यह साफ दिखाई देता है कि हरियाणा आज भी आर्थिक प्रबंधन और विकास के मामले में कहीं अधिक संतुलित और मजबूत स्थिति में है। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में बजट पर चर्चा के उपरांत जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-05 में जब हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थीं, उस समय हरियाणा का कुल बजट 15 हजार 526 करोड़ रुपये था। जबकि, पंजाब का बजट 25 हजार 627 करोड़ रुपये था अर्थात उस समय पंजाब का बजट हरियाणा की तुलना में अधिक था। यदि उस समय के सरकारी ऋण की बात करें तो हरियाणा का कुल ऋण 17 हजार 347 करोड़ रुपये था, जो बजट का लगभग 112 प्रतिशत था। जबकि, पंजाब का कुल ऋण 37 हजार 796 करोड़ रुपये था, जो उनके बजट का लगभग 147 प्रतिशत था। इसका अर्थ यह है कि उस समय भी पंजाब की वित्तीय स्थिति हरियाणा की तुलना में अधिक दबाव में थी। वर्ष 2005-06 और 2006-07 में भी यही स्थिति बनी रही, जब हरियाणा में कांग्रेस सरकार का

बजट पंजाब की कांग्रेस सरकार से कम था परंतु पंजाब के बजट का ऋण प्रतिशत हरियाणा से ज्यादा था। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि हम हाल के वर्षों की स्थिति देखें तो वर्ष 2021-22 में जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हरियाणा का बजट 1 लाख 35 हजार 910 करोड़ रुपये था और कुल ऋण बजट का लगभग 167 प्रतिशत था। वहीं, पंजाब का बजट हरियाणा से कम होकर 1 लाख 25 हजार 501 करोड़ रुपये था, लेकिन उसका कुल ऋण बजट का लगभग 186 प्रतिशत था अर्थात उस समय भी पंजाब पर कर्ज का बोझ हरियाणा की तुलना में अधिक था जबकि हरियाणा का बजट पंजाब से ज्यादा हो गया था। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान स्थिति देखें तो यह अंतर और स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा का कुल बजट 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ रुपये है और कुल ऋण बजट का लगभग 175 प्रतिशत है। वहीं, दूसरी ओर पंजाब का कुल बजट केवल 1 लाख 80 हजार 437 करोड़ रुपये है। लेकिन, उसका कुल ऋण उसके बजट का लगभग 248 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास की गति को भी तेज किया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि जैसे सभी क्षेत्रों में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम प्रदेश की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने हरियाणा प्रदेश पर भी कर्ज के बारे में अलग–अलग आंकड़े देकर सदन और प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि वर्ष 2014-15 का लोन 96 हजार 875 करोड़ (70,925+25,950), जो 2014-15 की जी.एस.डी.पी. 4 लाख 37 हजार 145 करोड रुपये का 22.16 प्रतिशत बनता है। उस समय वित्त आयोग की ऋण लेने की सीमा थी 22.9 प्रतिशत।

विपक्ष के आरोप तथ्यहीन, हरियाणा की वित्तीय स्थिति मजबूत

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट 2026-27 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप तथ्यों से परे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को गति दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा यह कहा गया कि प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2014-15 में राज्य पर 96 हजार 875 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो उस समय की 4 लाख 37 हजार 145 करोड़ रुपये की जीएसडीपी का 22.16 प्रतिशत था। उस समय वित्त आयोग द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 22.9 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस सीमा से ऊपर कर्ज ले रखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कांग्रेस विधायकों ने राज्य की ऋण देनदारी को लेकर भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और कर्ज को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी ऋण संबंधी आंकड़े सीएजी और आरबीआई की रिपोर्ट तथा राज्य के वार्षिक बजट दस्तावेजों में उपलब्ध हैं, जो सार्वजनिक रूप से देखे जा सकते हैं। इसलिए कर्ज को लेकर अलग से श्वेत पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री नायब सिंह सैनी ने बजट में वृद्धि को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह कहना कि महंगाई दर को हटाने के बाद बजट में केवल 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है, सही नहीं है। यदि वर्ष 2022-23 की कीमतों के आधार पर तुलना की जाए तो वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान 1 लाख 93 हजार 294 करोड़ रुपये और संशोधित बजट 1 लाख 91 हजार 156 करोड़ रुपये बनता है। इसी प्रकार वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान 2 लाख 8 हजार 831 करोड़ रुपये है। इस प्रकार वास्तविक रूप से वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 8 प्रतिशत तथा संशोधित बजट की तुलना में 9.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने आय बढ़ाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं और आबकारी से संबंधित वसूली पर भी टिप्पणी की है।

शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में नहीं होगी कोई कटौती : मुख्यमंत्री सुक्खू

कहा, बदलते समय में विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास विकसित करना बेहद जरूरी

दूरदराज क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं: सीएम

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट में कोई कटौती नहीं करेगी। उन्होंने साफ किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि दूरदराज क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। शिमला में मंगलवार को आयोजित एक दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय में विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास विकसित करना बेहद जरूरी है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था की भूमिका सबसे अहम है। सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कई नई पहलें शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में विशेष विषयों के महाविद्यालय खोलने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर में 50 बीघा भूमि पर एक विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, वाणिज्य और अन्य विषयों के विशेष कॉलेज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए खाली पदों को भरना भी प्राथमिकता में है। उन्होंने जानकारी दी कि सहायक प्राध्यापकों के 400 और जूनियर सहायक प्राध्यापकों के 400 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही कॉलेजों में न्यू एज पाठ्यक्रम और अतिरिक्त भाषा कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ सके। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रैंकिंग प्रणाली भी लागू की गई है, जैसा कि स्कूलों में किया गया है। इसी क्रम में सम्मेलन के दौरान राजकीय महाविद्यालयों की आंतरिक रैंकिंग भी जारी की गई।

समग्र रैंकिंग में राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर पहले स्थान पर रहा, जबकि संजौली कॉलेज दूसरे और राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला तीसरे स्थान पर रहा। अलग-अलग टियर में भी विभिन्न कॉलेजों को शीर्ष स्थान मिला और सभी विजेता कॉलेजों को एक-एक लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग का पुनर्गठन करते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय अलग-अलग स्थापित किए गए हैं, ताकि कामकाज में बेहतर समन्वय और दक्षता लाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के शिक्षक सक्षम हैं और ये सुधार उन्हें और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनें स्थापित की गई हैं और चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्थिति पर भी बात की और कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया है और 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी नहीं दी गई।

हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में गूंजेंगे 834 सवाल

18 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा सत्र

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में इस बार कुल 834 सवाल सरकार के सामने रखे जाएंगे। इनमें 665 तारांकित और 169 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इन सवालों में पिछले चरण के 125 प्रश्न भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा अलग-अलग नियमों के तहत कई नोटिस भी दिए गए हैंएक महीने के अंतराल के बाद चौदहवीं विधानसभा के 11वें सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से सुबह 11 बजे शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस चरण में कुल 13 बैठकें होंगी और पहले चरण की 3 बैठकों को मिलाकर पूरे बजट सत्र में कुल 16 बैठकें आयोजित की जाएंगीसत्र की शुरूआत 18, 19 और 20 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से होगी। इस चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 मार्च को देंगे। इसके बाद 21 मार्च को मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे, जो इस सत्र का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। बजट पेश होने के बाद 23, 24 और 25 मार्च को उस पर सामान्य चर्चा होगी। 25 मार्च को इस चर्चा का समापन किया जाएगा। इसके बाद 27, 28 और 30 मार्च को बजट की मांगों पर विस्तार से चर्चा और मतदान होगा।

30 मार्च को ही विनियोग विधेयक पर विचार-विमर्श के बाद इसे पारित किया जाएगा। वहीं 31 मार्च को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस रखा गया है, जबकि 1 और 2 अप्रैल को शासकीय और विधायी कार्य होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार सदस्यों द्वारा उठाए गए सवाल सीधे तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हैं। इनमें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, हिमाचल प्रदेश बोर्ड के स्कूलों को सीबीएसई में मिलाने का प्रस्ताव, सड़कों और पुलों का निर्माण, स्वीकृत परियोजनाओं की डीपीआर, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन, सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा पर्यटन, बागवानी, पेयजल आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या, बढ़ते अपराध, सौर ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था जैसे विषय भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे।

कई विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय मुद्दों को भी प्रश्नों के जरिए सामने रखा है। पठानिया ने कहा कि सभी प्रश्न और सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुई हैं और उन्हें नियमों के अनुसार सरकार को भेज दिया गया है, ताकि संबंधित विभाग समय पर जवाब तैयार कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि नियम-62 के तहत 8, नियम-101 के तहत 3 और नियम-130 के तहत 5 नोटिस भी मिले हैं, जिन पर भी सदन में चर्चा संभव है विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सत्र को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चलाना सभी की जिम्मेदारी है।

एफसीए के तहत अभी तक 30 प्रस्तावों को मिल चुकी है अंतिम स्वीकृतिः अपूर्व देवगन

एजेंसी (हि.स.)

मंडी

वन संरक्षण अधिनियम एफसीए के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा के लिए उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में यहां एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं से संबंधित एफसीए मामलों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा उनके शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गएउपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी से बचने के लिए एफसीए प्रस्तावों का समयबद्ध निपटारा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च, 2023 से अब तक जिले के विभिन्न विभागों के कुल 30 प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से एक प्रस्ताव को फरवरी माह में तथा दो प्रस्तावों को मार्च माह में स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें सलापड़-तत्तापानी सड़क, प्रस्तावित करसोग न्यायालय परिसर तथा पधर न्यायालय परिसर शामिल हैंउन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रत्येक लंबित प्रस्ताव के लिए स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की जाए और निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सज गए मां के दरबार, अब श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार कठुआ

कठुआ। आगामी वीरवार से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर जिला कठुआ के सभी प्रमुख मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिले भर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और हर तरफ श्रद्धा व उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा हैकठुआ के जसरोटा स्थित काली माता मंदिर, बिलावर में बाला सुंदरी माता मंदिर, सुकराला माता मंदिर, बनी का जोड़ियां माता मंदिर, नगरी का बाला सुंदरी मंदिर सहित कठुआ शहर, विभिन्न तहसीलों बिलावर, बसोहली और हीरानगर के मंदिरों में रंग-रोगन और सजावट का कार्य पूरा हो चुका है। मंदिरों को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है, जिससे रात के समय पूरा वातावरण जगमगा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही सभी विभागों को नवरात्रि के दौरान अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभाने के निर्देश जारी किए गए हैंपुलिस प्रशासन ने सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जबकि बिजली विभाग को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग को श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था सुचारु रखने को कहा गया है।

अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ लोकेशन भेजकर होती थी चिट्टा की सप्लाई

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

शिमला जिले में पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का पदार्फाश करने का दावा किया है, जो लोकेशन-बेस्ड डिलीवरी के जरिए नशे की सप्लाई कर रहा था। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क में नशे को अलग-अलग जगहों पर छिपाकर उसकी लोकेशन ग्राहकों तक भेजी जाती थी। इससे वे वहां से खुद ही मादक पदार्थ उठा लेते थेमामले में पुलिस ने पंजाब के अमृतसर से 34 वर्षीय लुकास नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसे इस नेटवर्क का मुख्य सप्लायर बताया जा रहा है। उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और सात सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन डिजिटल उपकरणों की जांच से नेटवर्क के और लिंक सामने आ सकते हैं। पुलिस के मुताबिक यह मामला थाना जुब्बल में दर्ज एक केस से सामने आया। 9 फरवरी को एनएच-705 पर गश्त के दौरान बौली नाला के पास पुलिस ने एक 20 वर्षीय युवती को संदिग्ध हालत में पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 13.46 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ, जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण किया। इन डिजिटल साक्ष्यों से पता चला कि युवती के संपर्क पंजाब के ड्रग तस्करों से थे और यह नेटवर्क जुब्बल-रोहड़ू क्षेत्र के कुछ स्थानीय युवाओं तक फैला हुआ था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवती का काम नशे की खेप को अलग-अलग जगहों पर छिपाना और उन स्थानों की फोटो या वीडियो बनाकर मुख्य सप्लायर को भेजना था। इसके बाद सप्लायर वही लोकेशन ग्राहकों को भेज देता था। पुलिस का कहना है कि इस तरह का यह संगठित लोकेशन-बेस्ड डिलीवरी मॉड्यूल्अब ध्वस्त कर दिया गया है। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर पंजाब के मोहाली, खरड़ और अमृतसर में लगातार दबिश दी, जिसके बाद मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी संभव हो सकी। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय था।

संक्षिप्त-समाचार

गोजातीय तस्करी के प्रयास विफल, 23 गोवंश को बचाया

जम्मू। ऑपरेशन कामधेनु के तहत अपने गहन अभियान को जारी रखते हुए जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने पुलिस स्टेशन झज्जर कोटली और पुलिस स्टेशन नगरोटा के अधिकार क्षेत्र में तीन गोजातीय तस्करी के प्रयासों को विफल करके कुल 23 गोजातीय जानवरों को बचाकर बड़ी सफलता हासिल की। पहली घटना में नाका पॉइंट पंजाल पर नियमित वाहन चेकिंग के दौरान, पुलिस स्टेशन झज्जर कोटली की एक पुलिस टीम ने एक महिंद्रा बोलेरो लोड कैरियर (जेके06बी-2558) को रोका। नाका देखकर चालक मौके से भाग गया। चेकिंग के दौरान 03 गोवंश बरामद हुए। जानवरों को बचा लिया गया और वाहन जब्त कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन झज्जर कोटली में धारा 223 बीएनएस और धारा 11 पीसीए अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 32/2026दर्ज की गई है। उसी नाका बिंदु पर एक अन्य घटना में एक पुलिस टीम ने एक महिंद्रा लोड कैरियर *(जेके02सीएन-0704) को रोका, पुलिस की उपस्थिति को देखकर चालक मौके से भाग गया। चेकिंग के दौरान कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 04 गोवंश लदे पाए गए। जानवरों को बचा लिया गया और वाहन जब्त कर लिया गया। तदनुसार, धारा 223 बीएनएस और धारा 11 पीसीए अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 33/2026 पुलिस स्टेशन झज्जर कोटली में दर्ज की गई

कालाअंब की कंपनी में मैनेजर, केमिस्ट और ऑपरेटर सहित 28 पदों पर भर्ती

नाहन। रोजगार कार्यालय के माध्यम से मैसर्ज वरव बायोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड, कालाअंब सिरमौर में 02 पद मेनेजर, 01 सीनियर एग्जीक्यूटिव, 12 केमिस्ट, 11 ऑपरेटर तथा 02 पद इलेक्ट्रीशियन के भरे जाने है। इन पदों के लिए साक्षात्कार 20 मार्च 2026 को उपरोजगार कार्यालय पांवटा साहिब में प्रातः 10:30 बजे से आयोजित किए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी देविन्द्र कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अनुभवी और योग्य उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, मैनेजर के दो पदों के लिए बी.फार्मा या एम.फार्मा के साथ 15 से 20 वर्ष का लंबा अनुभव अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए 1 लाख रुपये का आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। वहीं, सीनियर एग्जीक्यूटिव के एक पद के लिए बी.फार्मा या एम.फार्मा की डिग्री और 8 से 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को 35 से 40 हजार रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। केमिस्ट के 12 पदों के लिए बी.फार्मा, एम.फार्मा, बी.एससी या एम.एससी की योग्यता के साथ 03 से 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है

106वें स्थापना दिवस पर कांगड़ा बैंक ने शुरू की कम ब्याज दर वाली ई-वाहन ऋण योजना

धर्मशाला। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (केसीसी) के 106वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर बैंक ने ई वाहनों के लिए बाजार में सबसे कम ब्याज दरों पर ऋण योजना की शुरूआत की है। मंगलवार को बैंक के प्रबंध निदेशक जफर इकबाल ने एक नई ऋण योजना कांगड़ा बैंक ई-वाहन ऋण योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह योजना व्यक्तिगत उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों की खरीद हेतु वित्तपोषण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने धर्मशाला स्थित मुख्य कार्यालय के सभागार में स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रबंध निदेशक जफर इकबाल ने कहा कि यह योजना, बाजार में सबसे कम ब्याज दरों में से प्रदान करती है। यह इसे सभी वर्गों के ग्राहकों के लिए अत्यंत आकर्षक और किफायती बनाती है इसमें ब्याज दर पर साढ़े सात प्रतिशत निर्धारित की गई है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों, निजी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यापारियों, किसानों और अन्य पात्र उधारकताओं के लिए उपलब्ध रहेगी।

रेणुका बांध विस्थापितों का फूटा गुस्सा, डांडा-अंबोया में जमीन की निशानदेही बीच में रोकी

नाहन। रेणुका जी बांध परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों और प्रशासन के बीच जमीन आवंटन का मामला एक बार फिर गरमा गया है। मंगलवार को डांडा-अंबोया में विस्थापितों को दी जाने वाली जमीन की डिमार्केशन (निशानदेही) के दौरान विस्थापित परिवारों ने भारी नाराजगी जताते हुए प्रक्रिया को बीच में ही रुकवा दिया। विस्थापितों का आरोप है कि उन्हें कागजों में जो जमीन दिखाई गई थी, धरातल पर उसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत और अनुपयुक्त है। मौके पर स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब विस्थापितों ने पाया कि आवंटित की जाने वाली जमीन के बीचों-बीच स्थानीय निवासियों की निजी भूमि भी शामिल है। इसके कारण मौके पर ही विवाद की स्थिति बन गई और स्थानीय लोगों ने भी इस प्रक्रिया पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विस्थापित परिवारों ने एकजुट होकर प्रशासन और एचपीपीसीएल के खिलाफ अपना विरोध जताया। विस्थापितों का कहना है कि प्रशासन ने कागजों में जिस जमीन को कुलाऊ (उपजाऊ/सिंचित) बताया था, वह वास्तव में बंजर और पथरीली निकली। मौके पर न तो पानी की कोई व्यवस्था है और न ही वहां तक पहुंचने के लिए सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुविधाओं के अभाव और जमीन की खराब गुणवत्ता के कारण सभी विस्थापित परिवारों ने सर्वसम्मति से इस 248 बीघा जमीन को लेने से साफ इनकार कर दिया और डिमार्केशन छोड़कर वापस लौट गए। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने कड़े शब्दों में कहा कि विस्थापितों के साथ इस तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक विस्थापितों को वादे के अनुरूप उचित और उपजाऊ जमीन नहीं दी जाती, तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा।

सरकार के लिए मुश्किलों भरा रहेगा बजट सत्र हर सवाल का देना होगा जवाबः जयराम ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत से एक दिन पहले ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सत्र सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं रहने वाला है और सरकार को सदन में हर सवाल का जवाब देना होगा।

शिमला में मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर नोटिस दिए हैं, जिनमें कानून व्यवस्था, विकास कार्यों में कमी और आर्थिक स्थिति जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है और वह लगातार सदन को गुमराह कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार परंपराओं के विपरीत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को लंबित रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार खुद असमंजस की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है और सरकार इस पर स्पष्टता देने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष इन सभी मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएगी और सरकार को जवाब देना ही होगा। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयानों को विशेषाधिकार हनन का मामला माना जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में धारा 118 के नाम पर लोगों को गुमराह कर पैसे वसूलने वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिससे आम जनता परेशान है। उद्योगों के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश से उद्योगों का पलायन जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बावजूद कई संस्थानों के बंद होने का सिलसिला थमा नहीं है, जो चिंता का विषय है। जयराम ठाकुर ने एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर करने के फैसले पर भी सवाल उठाए।

जीएमसी कठुआ से 50 वर्षीय महिला रहस्यमयी ढंग से लापता

कठुआ। जीएमसी कठुआ में उपचाराधीन एक 50 वर्षीय महिला के अचानक लापता हो जाने का मामला सामने आया है, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और परिजन बेहद परेशान हैं। जानकारी के अनुसार सांझी मोड़ कठुआ निवासी रहमती बेगम पिछले चार दिनों से जीएमसी कठुआ में भर्ती थीं और उनका इलाज चल रहा था। उनके साथ दो तीमारदार भी मौजूद थे। मंगलवार सुबह करीब 5रू30 बजे, जब एक तीमारदार कैंटीन में चाय लेने गया हुआ था और दूसरा वहीं मौजूद था, इसी दौरान रहमती बेगम अचानक वार्ड से बाहर निकल गईं और उसके बाद वापस नहीं लौटीं। काफी तलाश के बावजूद जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने तुरंत अस्पताल परिसर और आसपास खोजबीन शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस चैकी में शिकायत दर्ज करवाई। महिला के परिजन सैफ अली ने बताया कि उनकी मरीज बिना बताए अस्पताल से बाहर चली गई और तब से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी तलाश कर महिला को सुरक्षित ढूंढा जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में महिला की तलाश की जा रही है।

पंचायत चुनावों में गैर-स्थानीय मतदाता और उम्मीदवार मंजूर नहीं: शिवसेना

एजेंसी (हि.स.)

जम्मू

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ताजा जनगणना और पारदर्शी परिसीमन के बिना चुनाव कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थानीय अधिकारों के साथ अन्याय होगा। इसके साथ ही पार्टी ने पंचायत चुनावों में गैर-स्थानीय व्यक्तियों को मतदाता या उम्मीदवार बनाने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया हैपार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि प्रशासन अभी भी वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है जो पूरी तरह अनुचित है। पिछड़े वर्गों (ओबी सी) को न्यायसंगत आरक्षण तभी मिल सकता है जब प्रशासन के पास नवीन और सटीक जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध हों। वही मतदाता सूची के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए साहनी ने स्पष्ट कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में बाहरी व्यक्तियों को मतदाता या उम्मीदवार बनाने की किसी भी कोशिश को शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी उन्होंने कहा कि केवल वैध डोमिसाइल धारकों को ही मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि स्थानीय निकायों पर पहला अधिकार जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों का है।

75 वर्ष बाद टूटा इंतजार, फराल चफादेयां को मिली पहली सड़क, जसरोटिया ने किया शुभारंभ

एजेंसी (हि.स.)

कठुआ

दूरदराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ने फराल से चफादेयां तक बनने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का शुभारंभ किया। करीब 80 लाख रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क आजादी के बाद इस क्षेत्र की पहली सड़क होगी, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया। यह परियोजना लोक निर्माण विभाग डिवीजन कठुआ द्वारा यूटी कैपेक्स बजट 2025-26 के तहत क्रियान्वित की जाएगी। सड़क बनने से दूरस्थ गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आवागमन आसान होगा और लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। स्थानीय निवासियों ने इसे वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जैसा बताते हुए कहा कि सड़क न होने के कारण उन्हें आपातकालीन स्थितियों और खराब मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नई सड़क से न केवल रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

मौसम **हिमाचल में 3 दिन और भारी बारिश, ओलावृष्टि-आंधी का अलर्ट**

केलंग से अटल टनल तक वाहनों की आवाजाही बंद

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

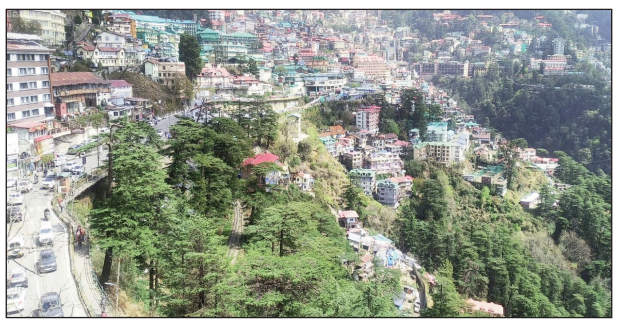

हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर तीखे बने हुए हैं और मार्च के महीने में ठंड ने दिसंबर जैसा एहसास करा दिया है। बीती रात राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मंगलवार को भी मौसम खराब बना हुआ है। शिमला, मनाली समेत अधिकांश पहाड़ी इलाकों में सुबह से बादल छाए हैं और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया हैइस बीच लाहौल-स्पीति प्रशासन ने हालात को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से जारी आदेश के अनुसार भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ और खराब विजिबिलिटी के कारण केलांग से अटल टनल तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि इस मार्ग पर यात्रा करना फिलहाल जोखिम भरा है और लोगों की जान-माल को खतरा हो सकता है। आदेश में यह भी बताया गया है कि सिस्सू के पास बैरियर लगाकर वाहनों की आवाजाही को रोका जाएगा। केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड और बीआरओ को ही सीमित रूप से आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, स्थानीय निवासियों के लिए भी केवल 474 वाहनों को ही छूट दी गई है। प्रशासन ने फंसे हुए वाहनों को प्राथमिकता से निकालने के निर्देश दिए हैं और बर्फ हटाने का काम तेज करने के लिए सुबह के समय सड़क को पूरी तरह खाली रखने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में मौसम और बिगड़ने की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में आज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अगले दो दिनों में मौसम के तेवर और तीखे हो सकते हैं। 18 और 19 मार्च को लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर राज्य के बाकी 10 जिलों में भारी बारिश, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है। इनमें 19 मार्च को मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इस दिन चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। वहीं हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट रहेगा। 20 मार्च को भी 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले तीन दिनों से राज्य में लगातार बदलते मौसम के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि मार्च के मध्य में ही सर्दी ने फिर से दस्तक दे दी है। मौसम के इस बदले मिजाज ने आम जनजीवन पर असर डाला है, खासकर पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही प्रभावित हुई है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।

संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

सदन से कांग्रेस के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री का तंज, बोले– विपक्ष गैर जिम्मेदार

विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, रचनात्मक सुझाव देने की बजाय वॉकआउट की राजनीति कर रही कांग्रेस

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश की जनता देख रही है जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक सदन में झूठ बोलकर सदन से वॉक आउट कर जाते हैं। कांग्रेस की फितरत रही है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। उन्होंने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो घर को क्या संभालेंगे। हम पर झूठे आरोप लगाकर वह भाग जाते हैं। विपक्ष का यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट अनुमान 2026–27 पर चर्चा के उपरांत जवाब दे रहे थे।

कांग्रेस विधायकों द्वारा सदन से वॉकआउट करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी सदस्य पता नहीं किस चश्मे से बजट को देख रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए बजट पर निराधार टिप्पणियां कर रहे हैं। विपक्ष ने बजट को गंभीरता से नहीं पढ़ा उन्हें यही नहीं पता कि बजट में विकास के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं तो वे प्रदेश की समस्याओं पर कैसे चर्चा कर सकते थे। जो सड़क पर आरोप लगाते हैं, उन्हीं आरोपों को सदन में बोल देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग इस महान सदन की तरफ आशा भरी नजर से देखते हैं, परंतु विपक्ष का यह गैरजिम्मेदाराना रवैया हरियाणा प्रदेश के लोग देख रहे हैं। विपक्ष को रचनात्मक सुझाव नहीं देने है, बल्कि झूठ बोलकर के सदन से भाग जाना है, यही विपक्ष की सोच है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस की भूमिका चिंताजनक है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल हाजिरी लगवानी है, विरोध करना है और झूठ फैलाना है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि– जो खुद चल नहीं पाते रास्तों पर, अक्सर वही मंजिलों पर सवाल करते हैं।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की खुद की मजबूरी है, क्योंकि विपक्ष को खुद सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई देना पड़ता है। पर काश, वे जनहित में कोई रचनात्मक सुझाव भी देते, कम से कम

उनके हलके के लोग तो उन्हें हल्के में न लेते। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. रघुबीर कादियान का बजट भाषण बहुत लंबा लगा, इन्होंने कहा कि बजट स्पीच 3 घंटे 9 मिनट की थी, यह विधानसभा का एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. रघुबीर कादियान सबसे सीनियर सदस्य हैं। इस सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे बताएं कि क्या बजट अभिभाषण को समय सीमा तय करने के लिए कोई फार्मूला है या क्या कांग्रेस के कार्यकाल में इसकी कोई समय सीमा तय की गई थी। इसे घंटों व मिनटों में तोलकर ऐसे अपमानित न करें। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरा यह दूसरा बजट प्रदेश के सभी हितधारकों के सुझावों को मिलाकर बनाया गया था।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों द्वारा राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने के संबंध में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी श्री संजय भाटिया को जीता कर दिल्ली भेजने का काम किया है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमने निर्दलीय उम्मीदवार को स्पोर्ट किया। विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर लेते, क्यों नहीं खड़ा किया। निर्दलीय उम्मीदवार हमारे पास वोट मांगने के लिए आया तो हमने उसे स्पोर्ट किया, इसमें विपक्ष को आपत्ति क्या है। डॉ रघुबीर कादियान ने आज भी चुनाव जीत कर भी चुनावी प्रक्रिया को कांड बताया, वोट चोरी की बात की। जबकि सच्चाई यह है कि न वोट चोरी होती है, न ईवीएम में मोरी होती है, लोकतंत्र में जनता की यही तो खूबी है जनाब, जगा देती है अंतरआत्मा, अगर वो सो रही होती है। इस प्रकार के आरोप लगाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. रघुबीर कादियान द्वारा आरोप लगाया गया कि प्री-बजट परामर्श बैठक केवल बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ ही कीं। जबकि किसानों और किसान संगठनों से कोई संवाद नहीं किया गया। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह आरोप सरासर गलत है। गत 15 जनवरी को हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्री-बजट परामर्श बैठक मैंने की थी। इसमें 362 किसान, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, एफपीओ, प्रगतिशील किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि शोधकर्ताओं ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त, गत 22 जनवरी को कुरुक्षेत्र में आयोजित प्री-बजट परामर्श बैठक में भी भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और किसानों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण सुझाव रखे। इसलिए यह कहना कि सरकार केवल उद्योगपतियों से मिलकर बजट बना रही है, न केवल तथ्यहीन है बल्कि उन हजारों किसानों, किसान संगठनों और विशेषज्ञों के योगदान का भी अपमान है, जिन्होंने अपनी मेहनत और अनुभव से बहुमूल्य सुझाव दिए। यह बजट किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि किसान, मजदूर, युवा, महिला, उद्योग और समाज के हर वर्ग की भागीदारी से तैयार किया गया है।

तीन दशक पुराने हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड से संबंधित विषय का कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया समाधानः नायब सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में बजट 2026-27 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा उठाया गया हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड से संबंधित विषय लगभग तीन दशकों से लंबित एक औद्योगिक इकाई और उससे जुड़े वित्तीय दायित्वों का मामला है। सरकार ने इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता, कानूनी प्रक्रिया और राज्य के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्तमान राज्य सरकार ने किसी भी स्तर पर न तो नियमों से समझौता किया है और न ही राज्य के हितों की अनदेखी की है। लगभग तीन दशक पुराने इस विवाद को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया गया और राज्य के हित में वर्ष 2000 से बकाया चली आ रही राशि को राज्य कोष में जमा करवाया। श्री नायब सिंह सैनी ने सदन को बताया कि वर्ष 1994 और 1995 के दौरान रोहतक स्थित मैसर्स हरियाणा टेलिकॉम लिमिटेड को राज्य के उद्योग विभाग द्वारा 18 करोड़ 68 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था। इस ऋण को औद्योगिक इकाई द्वारा पांच वर्ष की अवधि के बाद वापस करना था। कंपनी द्वारा केवल 39 लाख रुपये की राशि वापस की गई थी। शेष 18 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि वर्ष 2000 में वापस की जानी थी। लेकिन जून, 1999 में यह कंपनी दिवालिया घोषित हो गई और इसके बाद इसने सरकार को एक रुपये का ऋण भी वापिस नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में दिवालिया हुई कंपनी का एक और वित्तीय दायित्व जुड़ा हुआ था। मैसर्स परिवर्तन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी नामक एक अन्य कंपनी को भी मैसर्स हरियाणा टेलिकॉम लिमिटेड से 7 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि वसूल करनी थी। वर्ष 1998 में मैसर्स हरियाणा टेलिकॉम लिमिटेड ने अपनी 136 कनाल 8 मरला भूमि के संबंध में उद्योग विभाग, हरियाणा के साथ मॉर्गेज डीड निष्पादित की थी। इस मॉर्गेज में पहला चार्ज मैसर्स परिवर्तन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के पास था। जबकि, दूसरा चार्ज हरियाणा के उद्योग विभाग के पास था। जमीन गिरवी रखी प्राइवेट कंपनी को, सरकार ने दिया 18 करोड़ 68 लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन, पांच साल में सरकार को वापिस दिए सिर्फ 39 लाख रुपये। 1994 में तब कांग्रेस की सरकार थी।

चैत्र चौदस मेला को लेकर अधिकारी रखेंगे साफ सफाई पर फोकसःअनिल कुमार दून

सिटी दर्पण संवाददाता
पिहोवा

उपमंडल अधिकारी नागरिक अनिल कुमार दून ने कहा कि पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर 19 मार्च 2026तक चलने वाले चार दिवसीय चैत्र चौदस मेले में देश विदेश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाने के लिए पहुंच रहे है।अहम पहलू यह है कि 19 मार्च तक चलने वाले इस चैत्र चौदस मेले में श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए है। इस मेले के दौरान सभी अधिकारी साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे। एसडीएम अनिल कुमार दून इस चार दिवसीय चैत्र चौदस मेले के निरीक्षण करने उपरांत कर्मचारियों,अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।इससे पहले एसडीएम अनिल कुमार दून,नगरपालिका सचिव अशोक कुमार व डीएसपी निर्मल सिंह ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मुख्य बाजार व सरस्वती तीर्थ स्थल और प्रेत पीपल विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था को जांचा तथा कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। नगरपालिका सचिव अशोक ने कहा कि प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र रात्रि समय में भी साफ सफाई 50 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने सभी यात्रियों और तीर्थ पुरोहितो को अपील करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा पॉलिथीन,प्लास्टिक प्लेटो, गिलासों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए भंडारे में स्टिल या पत्तों से बने बर्तनों का प्रयोग करें ताकि गंदगी न फैले और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई परेशानी ना उठानी पड़े और मेले के सफल आयोजन में प्रशासन का सहयोग करें।

कला सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यमः प्रो. सोमनाथ सचदेवा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग द्वारा आयोजित 30वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन विश्वविद्यालय परिसर स्थित कला दीर्घा में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उनके साथ विभागाध्यक्ष डॉ. गुरचरण सिंह तथा आयोजन संयोजिका डॉ. मोनिका गुप्ता भी उपस्थित रहीं।

कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने अपने संबोधन में कहा कि कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक प्रभावशाली शक्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपनी रचनात्मकता का उपयोग सामाजिक संवाद, सांस्कृतिक समझ और व्यक्तिगत विकास के लिए करें। उन्होंने युवा कलाकारों के कार्यों की सराहना करते हुए उनमें तकनीकी दक्षता और गहन आत्मचिंतन के सुंदर समन्वय

को रेखांकित किया।

कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि समर्पण, नवाचार और निरंतर अभ्यास से विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं। ह्वभारतीय कला का स्वरूप निरंतर विकसित हो रहा है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत से लेकर समकालीन सामाजिक मुद्दों तक का समावेश है,ह्व उन्होंने कहा। कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने नवोदित कलाकारों से बड़े सपने देखने और अपनी रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

विभागाध्यक्ष डॉ. गुरचरण सिंह ने कहा कि यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच प्रदान करती है। यह आयोजन न केवल उनके कौशल को निखारता है बल्कि उनमें आत्मविश्वास का संचार करता है और नए विचारों को जन्म देता है।

इस प्रदर्शनी का आयोजन डॉ. मोनिका गुप्ता के कुशल नेतृत्व में किया गया, जिसमें छात्रों और शोधार्थियों द्वारा 300 से अधिक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में पारंपरिक लोक कला से लेकर आधुनिक डिजिटल प्रिंटमेकिंग तक विविध माध्यमों की उत्कृष्ट कृतियां शामिल हैं। प्रदर्शनी में चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंटमेकिंग, डिजिटल कला, फोटोग्राफी, वस्त्र कला और विज्ञापन डिजाइन जैसी विधाओं का समावेश है, जो विद्यार्थियों के बहुआयामी प्रशिक्षण को दशार्ता है। कृतियों में सामाजिक विषयों, आत्म-अन्वेषण, आध्यात्मिकता और मानवीय संवेदनाओं का प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है।इस अवसर पर कुटा प्रधान डॉ. जितेंद्र कुमार खटकर, प्रो. परमेश कुमार, डॉ. हरविंदर सिंह लोंगोवाल, प्रो. दीपक बब्बर, डॉ. पवन कुमार, डॉ. जया दरोंडे, डॉ. राकेश बानी, डॉ. आर.के. सिंह, डॉ. आनंद जायसवाल, सुशील, चंद्रिमा दास, डॉ. इशु जिंदल, सोहन, ममता, डॉ. सविप, लवलीना, निधि, अनिल, साहिल, विपिन, डॉ. गुरिंदर मौजूद थे। यह प्रदर्शनी 20 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। कला प्रेमियों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों से अपील की गई है कि वे इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें।

संक्षिप्त-समाचार

प्रदेश में पिछले 5 साल में 32 खेल स्टेडियमों का करवाया गया है निर्माणः गौरव गौतम

चंडीगढ़। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश में 1,95,53,18,978 रुपये की लागत से 32 स्टेडियमों के निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के पास कलायत विधानसभा क्षेत्र के गांव बाता में एक राजीव गांधी खेल स्टेडियम स्थित है। इसकी मरम्मत के लिए खेल विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को 15,03,574 रुपये की राशि जारी की गई है। इस स्टेडियम की मरम्मत का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कलायत क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण की मांग के संबंध में जिला खेल अधिकारी, कैथल द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। उस व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार नगर समिति द्वारा दिखाई गई भूमि समतल नहीं थी तथा उस पर सफेदा के पेड़ खड़े थे। भूमि का क्षेत्रफल 4 एकड़ नहीं था तथा उस भूमि पर पहले से ही सरकारी कार्यालय बने हुए थे। इसलिए इस स्थान पर स्टेडियम का निर्माण संभव नहीं पाया गया। मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि गांव राजौंद में स्टेडियम निर्माण की मांग के संबंध में जिला खेल अधिकारी कैथल द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। उस व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका राजौंद के सचिव ने अवगत कराया कि स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। मंत्री ने कहा कि गांव तितरम में स्टेडियम निर्माण की मांग के संबंध में जिला खेल अधिकारी कैथल द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। ग्राम पंचायत तितरम के सरपंच द्वारा स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि दिखाई गई, लेकिन उस भूमि के ऊपर से हाई टेंशन बिजली की लाइन गुजर रही थी तथा वहां अन्य बिजली के तार और खंभे भी लगे हुए थे। इसलिए उक्त स्थल को स्टेडियम के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

जुलाना नगर पालिका भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज, जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नगर पालिका, जुलाना के प्रधान एवं संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज है और मामले की जांच प्रगति पर है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक श्रीमती विनेश फौगाट द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इसके अलावा, विधायक श्री घनश्याम दास द्वारा यमुनानगर में शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने बारे पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनानगर में ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर क्षेत्र के भीतर आ गया है, जहां आबादी का घनत्व काफी अधिक है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर को ऐसी उपयुक्त जगह पर विकसित किया जाए, जहां सड़क संपर्क सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं व्यापारियों को सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

साइबर क्राइम पर सख्ती, मामलों में आई कमी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ कार्य कर रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में साइबर क्राइम के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहां 6054 मामले सामने आए थे, वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 5000 रह गई, जो लगभग 17 प्रतिशत की गिरावट दशार्ती है। इसी प्रकार ठगी के मामलों में भी बड़ी कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में 9804 मामलों की तुलना में वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 6324 रह गई, जो करीब 36 प्रतिशत की कमी है। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक श्री आफताब अहमद द्वारा साइबर क्राइम से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च एवं गरिमामयी मंचः गंगवा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च एवं गरिमामयी मंच है, जहां प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता, अनुशासन और मयार्दा के साथ विस्तृत चर्चा की जाती है।उन्होंने कहा कि बजट सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी सत्र में प्रदेश की आर्थिक दिशा, विकास योजनाएं और नीतिगत फैसले तय किए जाते हैं, जो आमजन के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। श्री गंगवा मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर बरवाला विधानसभा क्षेत्र से आए पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि मंत्री रणबीर गंगवा स्वयं भी बरवाला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस अवसर पर पत्रकारों ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को नजदीक से देखा। उन्होंने प्रश्नकाल, शून्यकाल तथा विभिन्न विभागों से जुड़े विषयों पर होने वाली चचाओं का अवलोकन किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझा। इसके साथ ही पत्रकारों ने चंडीगढ़ स्थित विधानसभा भवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी वास्तुकला और निर्माण से जुड़े पहलुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जाना कि यह भवन न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की आधुनिक वास्तुकला और लोकतांत्रिक परंपराओं का भी प्रतीक है।

पत्रकारों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को करीब से देखना उनके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा। इससे उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि किस प्रकार जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सदन में उठाते हैं और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। बाद में पत्रकारों ने मंत्री रणबीर गंगवा से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की, जहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया तथा जलपान की व्यवस्था की गई। इस दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों, चल रही परियोजनाओं एवं विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति (सेंशन) को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने आश्वस्त किया कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आवश्यक परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुलाकात के दौरान पत्रकारों को मंत्री रणबीर गंगवा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। यह पूरा कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं आत्मीय वातावरण में संपन्न हुआ।

हरियाणा की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जल्द

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने जा रही है। इसके अलावा, आईओसी द्वारा पानीपत में पीपीपी मॉडल पर 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता की देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।

बैठक में बताया गया कि इस परियोजना के माध्यम से भारतीय तेल निगम लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी को ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दिसंबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पंचामृत संकल्पों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक में परियोजना को बिजली देने सम्बन्धी विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री जे. गणेशन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक डॉ. संगीत तेतरवाल भी मौजूद रहे।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य की नई उद्योग नीति बनाई जा रही है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को थर्स्ट सेक्टर में रखा गया है।

पानीपत में स्थापित की जा रही इस परियोजना से हरियाणा के औद्योगिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव आएगा। खास तौर पर रिफाइनिंग और इस्पात जैसे उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में सहायता मिलेगी। इससे हरियाणा को लो-कार्बन रिफाइनिंग और ग्रीन स्टील उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की साइट योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के कारण इस परियोजना से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होने की संभावना है। साथ ही, पानीपत और आसपास स्थित उर्वरक तथा अमोनिया इकाइयों को भी ग्रीन अमोनिया अपनाने से लाभ मिलेगा, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी।

युवा आपदा मित्र स्कीम के तहत आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर की तैयारीयों का लिया जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी ने जायजा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी ने कहा कि राजस्व विभाग की तरफ से 18 मार्च से 24 मार्च तक युवा आपदा मित्रा स्कीम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन 18 मार्च को सुबह 11 बजे किया जाएगा।इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा होंगे। जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी मंगलवार को राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिविर से संबंधित तैयारियों का जायजा ले रही थी। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि बुधवार से इस शिविर का उद्घाटन होगा और इस शिविर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की युवा आपदा मित्रा स्कीम के तहत राज्य सरकार की तरफ से 400 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इससे पहले 200 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।इस शिविर का उद्घाटन 18 मार्च को राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में होगा । उन्होंने बताया कि इसके अलावा शाहबाद के आर्य कन्या कॉलेज में भी 18 से 24 मार्च तक युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मौके पर राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कानून शिक्षा को सामाजिक सरोकारों और तकनीकी नवाचारों से जोड़ना समय की मांगः प्रो. सोमनाथ सचदेवा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विधि संस्थान में 25वीं वर्षगांठ (रजत जयंती) एवं विधि गाला (ला फेस्ट) का भव्य आयोजन कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम ने न केवल संस्थान की गौरवशाली यात्रा को रेखांकित किया, बल्कि कानून, शिक्षा और तकनीक के समन्वय पर सार्थक विमर्श भी प्रस्तुत किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने विधि संस्थान की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में कानून की शिक्षा केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक सरोकारों और तकनीकी नवाचारों से भी जोड़ा जाना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे न्याय, नैतिकता और जिम्मेदारी को अपने करियर का आधार बनाएं तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने विधि गाला के सफल आयोजन के लिए विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को बधाई भी दी।इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के सम्मान के साथ हुआ।

मुख्य अतिथि प्रो. रतन सिंह, कुलपति, जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बदलते समय में कानूनी पेशे की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि कानून केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे अपने ज्ञान को निरंतर अद्यतन रखें और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। साथ ही उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि एक सक्षम विधि विशेषज्ञ वही है, जो संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे।

मुख्य अतिथि मेजर जनरल दीप अहलावत, कुलपति, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हुए उसके सदुपयोग पर बल दिया। विधि संस्थान के निदेशक प्रो. अमित लूदरी ने स्वागत भाषण में संस्थान की 25 वर्षों की उपलब्धियों और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया।

समारोह में संस्थान के पूर्व निदेशक प्रो. वी.के. अग्रवाल, प्रो. एस.सी. गुप्ता, प्रो. राजपाल शर्मा, प्रो. दिलीप कुमार एवं प्रो. सुशीला देवी चौहान तथा विधि संकाय की डीन प्रो. प्रीति जैन सहित सभी फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विधि संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. रमेश सिरोही ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह ने विधि संस्थान की उपलब्धियों को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया।

विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं को तराशने का सशक्त मंच : प्रो. सोमनाथ सचदेवा

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल परिसर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फ्री स्टाइल महिला कुश्ती प्रतियोगिता 2025-2026 का बतौर मुख्यातिथि उद्घाटन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि खेल प्रतिभाओं को तराशने का एक सशक्त मंच भी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएँ, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और उत्कृष्ट खेल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से खेल भावना से खेल को खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि यह चैंपियनशिप निस्संदेह देश की महिला पहलवानों के लिए अपनी प्रतिभा को निखारने और नए कीर्तिमान स्थापित करने का सुनहरा अवसर साबित होगी। इस अवसर पर अर्जुन अवार्डी पहलवान राजेंद्र कुंमार ने भी खिलाड़ियों को अपने अनुभव साझा करते हुए प्रेरित किया और उन्हें अनुशासन, मेहनत व समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में केयू खेल निदेशक प्रो. दिनेश राणा ने मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए खेलों के क्षेत्र में केयू के स्वर्णिम इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यह केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि चैंपियनों को गढ़ने की भूमि भी है। वहीं खेल परिषद के अध्यक्ष डॉ अमित कुमार ने सभी आगंतुकों, खिलाड़ियों एवं सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस भव्य आयोजन का मंच संचालन अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच राजेश कुमार राजौंद द्वारा अत्यंत प्रभावशाली एवं सुसंगठित ढंग से किया गया, जिसने पूरे कार्यक्रम में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखा। इस मौके पर उपाध्यक्ष डॉ. सुशीला, नितिन सहगल, संदीप करोड़ा प्रतियोगिता के संचालक कुलवंत सिंह, सुखबीर सिंह सहित विभाग के सभी कोचेज एवं सहायक स्टाफ की गरिमामयी उपस्थिति रही।

संपादकीय — महिलाएं करती हैं पुरुषों से ज्यादा काम !: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने बदल दी मातृत्व अधिकारों की परिभाषा

भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर न्यायपालिका ने एक बार फिर महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व लाभ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट टिप्पणी की कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक घंटे काम करती हैं। अदालत ने यह भी माना कि महिलाओं का कार्य केवल दफ्तर तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे घर और परिवार की जिम्मेदारियों को भी समान रूप से निभाती हैं। इस महत्वपूर्ण अवलोकन के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व अधिकारों को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह मामला एक महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ से वंचित किए जाने से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मातृत्व को केवल एक व्यक्तिगत या निजी घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह समाज के अस्तित्व और निरंतरता से जुड़ा विषय है। इसलिए, मातृत्व से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि महिलाओं को उचित मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता है, तो यह न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके सम्मान और गरिमा के खिलाफ भी है। अपने फैसले में अदालत ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण कार्य वातावरण प्रदान करना है। अदालत ने कहा कि इस अधिनियम की व्याख्या संकीर्ण रूप में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी महिला को मातृत्व लाभ से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है। अदालत ने अपने फैसले में 'डबल बर्डन' यानी दोहरे कार्यभार की अवधारणा पर विशेष जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाज में महिलाएं न केवल पेशेवर जिम्मेदारियां निभाती हैं, बल्कि घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की सेवा और अन्य घरेलू कार्य भी करती हैं। इस कारण उनका कुल कार्यभार पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अदालत की यह टिप्पणी उस सामाजिक सच्चाई को उजागर करती है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अदालत ने मातृत्व लाभ को केवल जैविक मातृत्व तक सीमित नहीं रखा। न्यायालय ने संकेत दिया कि गोद लेने वाली माताओं और सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। यह दृष्टिकोण आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कानून की व्याख्या करने का उदाहरण है। भारत में महिला श्रम भागीदारी दर लंबे समय से चिंता का विषय रही है। विभिन्न रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यबल से बाहर हो जाती हैं, खासकर मातृत्व के बाद। इसका प्रमुख कारण कार्यस्थलों में पर्याप्त सुविधाओं और सहयोग का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलेगी, बल्कि संस्थानों पर भी सकारात्मक दबाव बनेगा कि वे अपनी नीतियों में बदलाव करें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में मातृत्व लाभ से जुड़ी नीतियों की समीक्षा की जा सकती है। कंपनियों को यह समझना होगा कि मातृत्व अवकाश कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि एक अनिवार्य अधिकार है। इसके अलावा, कार्यस्थलों पर क्रेच सुविधा, लचीले कार्य घंटे, वर्क-फ्रॉम-होम और पुनः कार्य में वापसी के लिए सहायक नीतियां भी विकसित करनी होंगी। यह निर्णय केवल कानूनी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव भी हो सकता है। लंबे समय से यह धारणा रही है कि महिलाओं का काम घर तक सीमित है और उनका आर्थिक योगदान गौण है। लेकिन अदालत की टिप्पणी इस सोच को चुनौती देती है और यह स्थापित करती है कि महिलाओं का काम चाहे वह घर के भीतर हो या बाहर–समान रूप से महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। हालांकि, इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। विशेषकर निजी क्षेत्र में, जहां लागत और उत्पादकता को प्राथमिकता दी जाती है, वहां मातृत्व लाभ को लागू करने में हिचकिचाहट देखी जा सकती है। ऐसे में सरकार और संबंधित नियामक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अदालत के निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाए और किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही समाज में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। जब तक लोगों की सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक केवल कानूनी प्रावधानों से पूर्ण न्याय संभव नहीं है। परिवार और समाज को यह समझना होगा कि महिलाओं का योगदान बहुआयामी है और उन्हें हर स्तर पर समर्थन मिलना चाहिए। अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह निर्णय न केवल मातृत्व लाभ को सुदृढ़ करता है, बल्कि यह भी स्वीकार करता है कि महिलाओं का कार्यभार और योगदान अक्सर अदृश्य रह जाता है। यह फैसला उस अदृश्य श्रम को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इस निर्णय के प्रभाव से भारत में अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और संवेदनशील कार्यस्थलों का निर्माण हो सकता है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो यह न केवल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगा।

परछाईयां: साहिर लुधियानवी की सृजन स्थली

विवेक शुक्ला (हि.स)

मुंबई कभी रुकती नहीं। यह शहर मानो समय की धड़कन पर दौड़ता रहता है–दिन-रात, बिना ठहरे, बिना थके। सड़कों पर भागती कारें, देर रात तक जगती रोशनियां और काम में डूबे लोग इस शहर की पहचान हैं। लेकिन जब आप जूहू की तरफ मुड़ते हैं और अरब सागर के किनारे पहुँचते हैं, तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। शहर का शोर पीछे छूट जाता है। हवा में एक धीमी नमी है और लहरें एक अनवरत संगीत रचती रहती हैं। इसी शांत इलाके में छिपा है वह घर, जहां मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने अपने जीवन का लंबा और रचनात्मक समय बिताया। उस घर का नाम है–'परछाईयां।'

'परछाईयां' की तलाश में

रास्ते में कई लोगों से पूछते हैं। कोई कंधे उचकाकर कहता है–'पता नहीं।' कोई मुस्कराकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिद है उस घर को देखने की, जहां साहिर ने अनेक कालजयी गीत और गजलें लिखीं। दीवारों को छूने की, उन कमरों की हवा में सांस लेने की। चलते रहते हैं, गलियों से गुजरते हैं। और अजीब संयोग–जैसे ही पूछना छोड़ देते हैं, रास्ता खुद खुल जाता है। अचानक एक बड़े, सलेटी रंग के शांत बंगले की नेमप्लेट पर नजर ठहर जाती है। काले अक्षरों में रोमन लिपि में लिखा है–'ParchhaiyanI।

'परछाईयां'- अर्थात साये। यह नाम पढ़ते ही साहिर की कई पंक्तियाँ जेहन में उभर आती हैं। उनकी शायरी में गहरी उदासी थी, पर वह उदासी निराशा नहीं, बल्कि संवेदना की रोशनी थी। यह बंगला लगभग पांच सौ वर्ग गज में फैला है। मुंबई में रहने वाले वास्तु विशेषज्ञ डॉ जे.पी. शर्मा. लालधागेवाले साहिर साहब के बंगले को गुजरे कई दशकों को देख रहे हैं। वे बताते हैं कि ' इसकी बालकनियों से कभी अरब सागर साफ दिखता होगा। ऊपर की मंज़िलों में साहिर अपनी मां के साथ रहते थे। शाम ढलती, समुद्र से ठंडी हवा आती और कमरों में किताबों, कागजों और स्याही की हल्की गंध फैल जाती। यही वह जगह थी जहां रातें जागती थीं और शब्द धीरे-धीरे कविता का रूप ले लेते थे।'

सृजन का माहौल और अमर गीत

इस घर के दरवाजे दोस्तों के लिए हमेशा खुले रहते थे। फिल्मकार, संगीतकार, कवि और शायर यहां आया करते। कोई धुन गुनगुनाता, कोई राजनीति पर बहस छेड़ देता, तो कोई नई कविता सुनाता। साहिर चुपचाप सुनते, फिर अचानक एक पंक्ति कहते–और कमरे में सन्नाटा छा जाता, क्योंकि वह पंक्ति सीधे दिल में उतरती थी। इसी माहौल में कई अमर फिल्मी गीत जन्मे। जैसे 'उड़ें जब-जब जुल्फें तेरी' (फिल्मः नौटंकी), जो प्रेम की मस्ती को बयां करता है, या 'तुमसा नहीं देखा' (फिल्मः तुमसा नहीं देखा), जिसमें साहिर की रोमांटिक संवेदना झलकती है।

उनकी पंक्तियाँ आदर्शों की टूटन, समाज की विडंबना और प्रेम की कोमलता को एक साथ बोलती थीं। उनकी कलम विरोध भी करती थी और इंसानियत की लौ बचाए रखती थी। फिल्म प्यासा के 'ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या ह' जैसे गीत इसी घर की दीवारों में गूँजे होंगे, जहां सामाजिक अन्याय पर उनकी तीखी टिप्पणियाँ शब्दों में ढलती थीं। या 'अभी ना जाओ छोड़ कर' (फिल्मः हम दोनों), जो प्रेम की उदासी और बेचैनी को इतनी गहराई से व्यक्त करता है कि सुनकर दिल भर आता है।

मां के प्रति समर्पण और व्यक्तिगत जीवन

साहिर का निजी संसार भी इसी घर में बसता था। उन्होंने विवाह नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मां सरदार बेगम थीं। कहा जाता है कि किसी भी बड़ी चर्चा या निर्णय से पहले वे मां की राय अवश्य सुनते थे। मेहमान बैठे हों, बहस चल रही हो–वे उठकर मां के कमरे में जाते और पूछते, 'आप क्या सोचती हैं?' मां के प्रति यह सम्मान उनके व्यक्तित्व की कोमलता को उजागर करता है। जब 1976 में उनकी मां का निधन हुआ, तो साहिर भीतर से खाली हो गए। चार वर्ष बाद, 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से उनका जीवन थम गया।

खामोशी और विरासत

साहिर के जाने के बाद 'परछाईयां' पर लंबी खामोशी छा गई। कभी जिन कमरों में संगीत और कविता की गूँज रहती थी, वहां सन्नाटा बस गया। विरासत को लेकर विवाद हुए, विशाल लाइब्रेरी बिखर गई। कुछ पांडुलिपियाँ संयोग से मिलीं, जिन्हें चाहने वालों ने सहेज लिया। आज यह बंगला थोड़ा थका हुआ खड़ा है, जैसे समय की धूल उस पर जम गई हो। फिर भी दीवारें उन शब्दों की आहट संभाले हुए हैं। नेमप्लेट पर लिखे 'परछाईयां' को छूते हुए लगता है कि सच्ची कविता दीवारों में नहीं, लोगों की स्मृतियों में रहती है।

शायद इसलिए यह घर आज भी एक स्मारक की तरह खड़ा है, याद दिलाता हुआ कि एक शायर की सच्ची विरासत उसकी कविताएं और लोगों के दिल होते हैं। और जब शब्द दिल से निकले हों, तो वे मुंबई की भीड़ में भी कभी खोते नहीं।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और जाने-माने स्तंभकार हैं।)

आपदा में अवसर खोजने की मानसिकता: समाज के लिए एक खतरनाक संकेत

कैलाश चन्द्र (हि.स)

मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह से भारत में एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति और बुकिंग से जुड़ी चर्चा अचानक सुर्खियों में आ गई। देश के अनेक हिस्सों से गैस सिलिंडर की कमी, बुकिंग में देरी और डिलीवरी में व्यवधान जैसी खबरें तेजी से फैलने लगीं। सोशल मीडिया पर लोगों की चिंता देखकर यह विषय राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया। कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाए कि सिलिंडर मिल नहीं रहे, डिलीवरी डेट आगे बढ़ रही है और एजेंसियों पर दबाव बढ़ चुका है। इसके विपरीत केंद्र और राज्य सरकारों ने बार-बार स्पष्ट किया कि देश में कोई वास्तविक कमी नहीं है, परंतु कुछ क्षेत्रों में अचानक बढ़ी मांग और डिमांड-सप्लाई असंतुलन से अस्थायी तनाव अवश्य देखा गया है। यही तनाव इस पूरी चर्चा की शुरूआत बना।

इन खबरों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा कि अचानक ऐसी स्थिति क्यों बनी? इसे समझने के लिए एलपीजी बुकिंग और सप्लाई के वास्तविक आंकड़ों को देखना आवश्यक है। मार्च 2026 के आरंभ में रोजाना LPG बुकिंग 5.5 मिलियन के औसत स्तर से बढ़कर 7.6 मिलियन तक पहुँच गई। यह लगभग 35-40 प्रतिशत की उछाल थी, जिसे विशेषज्ञों ने 'पैनिक बुकिंग' की श्रेणी में रखा। कई शहरों में बुकिंग 2-3 गुना तक बढ़ गई। एक प्रमुख महानगर में केवल छह दिनों के भीतर 12 लाख से अधिक बुकिंग दर्ज होना इसकी तीव्रता का प्रमाण था। दूसरी ओर सरकार का दावा था कि घरेलू सिलिंडर की डिलीवरी 2-2.5 दिन के सामान्य समय में ही हो रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है, जिसे कमी कहा जाए। इसका अर्थ यह था कि समस्या व्यापक राष्ट्रीय अभाव की नहीं, बल्कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अचानक मांग बढ़ने और वितरण प्रणाली पर बने अस्थायी दबाव की थी।

इस पूरे परिदृश्य के पीछे जो वास्तविक कारण उभरकर सामने आए, वे कई स्तरों पर काम कर रहे थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव था। मध्य-पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के मध्य बढ़ते संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित हुए। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए जहाजों में देरी, समुद्री बीमा लागत और जोखिम बढ़ने लगे। एलपीजी शिपमेंट का समय बढ़ा, जिससे भारतीय बंदरगाहों पर डिलीवरी शेड्यूल में भी देर हुई।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह था कि भारत आज भी छढ्ढ्रकी अपनी कुल घरेलू आवश्यकता का लगभग 60-65% आयात करता है। अर्थात वैश्विक अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारतीय उपभोक्ता तक पहुँच सकता है। बड़े आयातक देशों में तनाव, शिपमेंट विलंब, पोर्ट कंजेशन और बर्कारिंग समय का बढ़ना, इन सभी का प्रभाव सीधे घरेलू सप्लाई चेन पर पड़ा। इसके अतिरिक्त ट्रकों की कमी, स्थानीय परिवहन में देरी, कुछ क्षेत्रों में सड़क मरम्मत या मौसम अवरोध जैसी घरेलू परिस्थिति ने भी दबाव बढ़ाया।

तीसरा कारण मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव से उत्पन्न 'पैनिक बुकिंग' रहा। किसी भी संकट में यह मानवीय प्रतिक्रिया आमतौर पर देखी जाती है। जैसे ही कुछ उपभोक्ताओं ने देरी की बात साझा की, लोगों ने एक साथ अतिरिक्त सिलिंडर बुक करना शुरू कर दिया। कई परिवारों ने सुरक्षा कारणों से दो-तीन सिलिंडर अतिरिक्त बुक कर लिए। जबकि सामान्य परिस्थितियों में वे इतनी खपत नहीं करते। इस असामान्य मांग ने वितरण प्रणाली में तात्कालिक तनाव उत्पन्न किया और सामान्य चक्र बिगड़ गया।

इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने कई त्वरित कदम उठाए। सबसे पहले रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी प्रोपेन-ब्यूटेन स्ट्रीम्स को एलपीजी उत्पादन में परिवर्तित करें, ताकि घरेलू बाजार की जरूरतें तुरंत पूरी हों। इस निर्देश से घरेलू एलपीजी उत्पादन लगभग 25% तक बढ़ाने में सफलता मिली। इससे तत्काल राहत मिली और डोमेस्टिक सप्लाई बैलेंस मजबूत हुआ।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत घरेलू उपभोक्ता को प्राथमिकता देने और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने की कार्रवाई शुरू की गई। वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कृत्रिम कमी की आशंका को खत्म किया गया। तीसरा कदम बुकिंग नियमों में संशोधन का था। पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए बुकिंग गैप 25 दिन तक बढ़ाया गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 45 दिन तक भी बढ़ाया गया, जिससे बार-बार अनावश्यक बुकिंग रुक सके। इससे सिस्टम पर दबाव कम हुआ और जिन उपभोक्ताओं को वास्तव में सिलिंडर की जरूरत थी, उन्हें समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि जहां पीएनजी (पाइप्ड नैचरल गैस) उपलब्ध है वहाँ उपभोक्ता अस्थायी रूप से पीएनजी को प्राथमिकता दें, ताकि एलपीजी वितरण पर दबाव संतुलित किया जा सके। इसके साथ-साथ अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए प्रेस विज्ञप्तियों, मीडिया ब्रीफिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

इन सभी तात्कालिक उपायों ने संकट के विस्तार को रोका, लेकिन इस स्थिति का प्रभाव विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग दिखाई दिया। घरेलू उपभोक्ता, जिनके लिए सरकार प्राथमिकता देती है, उन्हें सामान्यतः 2-3 दिन की डिलीवरी चक्र में सिलिंडर मिलता रहा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अस्थायी देरी का अनुभव हुआ। दूसरी ओर व्यापारिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, विशेषकर होटल, रेस्टोरेंट और फूड उद्योग–को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति पर प्राथमिकता सीमित थी। कुछ छोटे व्यवसायों और एमएसएमई ने भी गैस की अनिश्चिता के कारण उत्पादन लागत बढ़ने की शिकायत की। इधर-उधर से ब्लैक मार्केटिंग की सूचनाएं भी मिलीं, हालांकि सरकार ने इन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया।

इस संकट के बीच कई मिथक भी उभरे, जिनमें प्रमुख था कि देश में गैस खत्म हो गई है। सरकारी आंकड़े और विशेषज्ञ रिपोर्टें इस दावे को स्पष्ट रूप से गलत साबित करती हैं। देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद था, और प्रमुख समस्या सप्लाई अभाव की नहीं बल्कि वितरण तनाव और पैनिक बुकिंग की थी। दूसरा मिथक यह था कि गैस आपूर्ति पूरी तरह रुक गई है, जबकि वास्तविकता यह थी कि देशभर में ट्रकिंग, रीफिलिंग और डिलीवरी कार्य एक सीमित देरी के साथ निरंतर जारी रहा।

इस अनुभव का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति अब पहले से अधिक परिपक्व और दीर्घकालिक दिशा में बढ़ रही है। भारत घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। आयात पोर्टफोलियो को मध्य-पूर्व पर अत्यधिक निर्भरता से हटाकर अमेरिका जैसे देशों की ओर विविधीकृत किया गया है। हाल ही में किया गया अमेरिका से एलपीजी आयात का दीर्घकालिक अनुबंध इस दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। यह विविधीकरण न केवल कीमतों को स्थिर करेगा, बल्कि भू-राजनीतिक तनावों के प्रभाव को भी काफी हद तक कम करेगा।

साथ ही PNG नेटवर्क के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएनजी का उपयोग बढ़ने से एलपीजी सिलिंडर पर निर्भरता कम होगी और घरेलू वितरण प्रणाली पर अचानक मांग का दबाव भी भविष्य में घटेगा। इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों, इंडक्शन तकनीक और ऊर्जा-कुशल घरेलू समाधानों को भी नीतिगत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस तरह ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ता सुविधा दोनों दिशाओं में काम जारी है।

अंततः, मार्च 2026 में जिस तरह एलपीजी संकट की चर्चा शुरू हुई, वह देश में किसी स्थायी अभाव का संकेत नहीं था। यह स्थिति वैश्विक तनाव, अस्थायी लॉजिस्टिक बाधाओं और सबसे अधिक पैनिक बुकिंग के कारण उत्पन्न हुई थी। सरकार, कंपनियों और उपभोक्ताओं के संतुलित व्यवहार ने स्थिति को जल्द नियंत्रित किया। अतः इस सम्पूर्ण घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी संयम और क्षमता दोनों रखती है। भविष्य की नीति ऊर्जा स्वतंत्रता, स्थायी आपूर्ति, आयात विविधीकरण और तकनीकी मजबूती की दिशा में और आगे बढ़ रही है। यह संकट एक चेतावनी अवश्य था, लेकिन साथ ही इसने यह भी सिद्ध किया कि भारत की ऊर्जा संरचना जितनी विशाल है, उतनी ही मजबूत भी।

आज का राशिफल

मेषः आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। व्यापार में स्थिति नरम रहेगी। शत्रुभय, ङ्कषचता, संतान को कष्ट, अपव्यय के कारण बनेंगे। भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर बना रहेगा। कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बनेगी। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। कामकाज में आ रही बाधा को दूर कर लेंगे। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा। मेहमानों का आगमन होगा। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। नैतिक दायरे में रहें। पुरानी गलती का पश्चाताप होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। धीरे-धीरे लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा उचित समय का इन्तजार करें। मेहमानों का आगमन होगा। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः आय के अच्छे योग बनेंगे। संतान की उन्नति के योग हैं। स्त्री-संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्र से मिलन होगा। स्वविवेक से कार्य करें। शत्रुपक्ष से सावधान रहें। भाई-बहनों का प्रेम बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। इच्छित कार्य सफल होंगे। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः आगे-आगे गौरख जागे" वाली कहावत चरितार्थ होगी। मेहमानों का आगमन होगा। परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल व समन्वय बनाय। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः जीवन साथी अथवा यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः लाभ में आशातीत वृद्धि तय है मगर नकारात्मक रुख न अपनाएं। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आय-व्यय समान रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

धनुः अर्थपक्ष मजबूत रहेगा। जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा। व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ कार्यों का लाभदायक परिणाम होगा। कामकाज की अधिकता रहेगी। व्यवसायिक अभ्युदय भी होगा और प्रसन्नताएं भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

मकरः कामकाज की व्यस्तता से सुख-आराम प्रभावित होगा। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। अवरुद्ध कार्य संपन्न हो जाएंगे। मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी। श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां होगी। यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः होश में रहकर कार्य करें। कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। कारोबारी यात्रा को फिलहाल टालें। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। अपने हितैषी समझे जाने वाले ही पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर बना रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

मीनः राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। कारोबारी यात्रा को फिलहाल टालें। शैक्षणिक कार्य आसानी से पूरे होते रहेंगे। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। श्रम साध्य कार्यों में सफल होंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनाने के लिए भाग-दौड़ रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

यूसीसी : समान नागरिक संहिता की गलत व्याख्या करते ओवैसी

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं के हक पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- 'अब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का समय आ गया है।' के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी का विरोध करते हुए कई बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि 'यूसीसी के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं किया जा सकता' और 'इस्लाम में शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, यह जन्म-जन्म का बंधन नहीं है। यह जिम्मेदारी नहीं है।...निकाह हमारे के लिए धार्मिक संस्कार नहीं है।'

अब सवाल यह है कि क्या यूसीसी वास्तव में किसी धर्म को निशाना बनाने की कोशिश है या फिर यह संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में एक कदम है? वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समान नागरिक कानून पहले से लागू है। ऐसे में ओवैसी का ये विरोध साफ बता रहा है कि वह देश में इस्लाम के नाम पर अपने लिए वे एक विशेष अधिकार चाहते हैं, वह देश की जनसंख्या में 20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी अल्पसंख्यक बने रहना चाहते हैं और उसमें भी वे रिलीजन के नाम पर अलग स्वतंत्रता चाहते हैं।

यहां सीधे तौर पर यहां स्पष्ट होता है कि उन्हें देश की समानता से कोई मतलब नहीं है! इसलिए वे यह भी कह रहे हैं कि यदि हिंदू विवाह कानून को आधार बनाकर यूसीसी लागू किया गया तो वह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। ओवैसी इतना कहने के बाद भी नहीं रुकते हैं, इसके अलावा भी वे बहुत कुछ कहते हैं। देखा जाए तो पहली नजर में ये बातें धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता के रूप में सामने आती हैं, लेकिन गहराई से देखने पर यह तर्क कई स्तरों पर सवालों के घेरे में आ जाता है।

ओवैसी का सबसे बड़ा तर्क यह है कि यूसीसी के नाम पर 'हिंदू कानून' मुसलमानों पर लागू किया जाएगा, लेकिन यह तर्क स्वयं ही गलत आधार पर खड़ा है। समान नागरिक संहिता का अर्थ किसी एक धर्म के कानून को दूसरे धर्म पर थोपना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है; एक ऐसा नागरिक कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों में समान नियम लागू होते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस व्यवस्था को समानता और लैंगिक न्याय को मजबूत करने का माध्यम माना जाता है।

यदि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दुनिया के अधिकांश देशों में किसी न किसी रूप में समान नागरिक कानून लागू है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में लगभग 193 देश हैं और इनमें से बड़ी संख्या में विवाह, तलाक और संपत्ति के मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग कानून नहीं हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, सपेन, पुर्तगाल, जापान, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, रूस, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में एक ही सिविल कोड सभी नागरिकों पर लागू होता है।

फ्रांस में तो इसे 1804 में ही लागू कर दिया था, नेपोलियन सिविल कोड आधुनिक सिविल कानून की नींव के चलते आगे इसके कारण से यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों की कानूनी व्यवस्था प्रभावित हुई। इन देशों में विवाह केवल सिविल प्रक्रिया के माध्यम से ही मान्य होता है और तलाक तथा संपत्ति के अधिकार भी एक समान कानून से नियंत्रित होते हैं। यही कारण है कि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में धर्म और कानून को अलग रखने की प्रवृत्ति अधिक मजबूत दिखाई देती है।

प्रश्न यह है कि यदि दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिक कानूनों को धर्म से अलग रखा गया है और सभी नागरिकों पर ये समान रूप से लागू होते हैं। वहां यदि इन समान कानूनों को लोकतंत्र और आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है, तब भारत में इसे 'धर्म पर हमला' बताना कितना तर्कसंगत है?

ऐसे में कहना यही होगा कि ओवैसी के बयान देखने में भले ही कानूनी तर्क की बात धार्मिक पहचान के आधार पर करता हुआ दिखाई दे, लेकिन यह सीधे तौर पर राजनीति है। जब वे कहते हैं कि 'मुझे अपने धर्म के मुताबिक चलना चाहिए', तो यह तर्क व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन यह भी सवाल उठाता है कि क्या नागरिक कानून केवल धार्मिक पहचान के आधार पर तय होना चाहिए?

अवैसी ये कैसे भूल सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां कानून का आधार नागरिकता है, न कि धर्म? अगर हर समुदाय अपने-अपने धार्मिक कानूनों के अनुसार अलग कानूनी व्यवस्था की मांग करेंगे तब फिर देश में समानता का संवैधानिक सिद्धांत कहां रह जाता है? यही कारण है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। संविधान निमार्ताओं का मानना था कि एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य में नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया के कई मुस्लिम-बहुल देशों में भी पारिवारिक कानून में बड़े सुधार हुए हैं। उदाहरण के लिए तुर्की ने 1926 में आधुनिक नागरिक कानून अपनाया और शरिया अदालतों को समाप्त कर दिया। इसी तरह ट्यूनीशिया ने 1956 में पर्सनल स्टेटस कोड लागू किया, जिसके तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए।

इस प्रकार वैश्विक अनुभव यह बताता है कि समान नागरिक संहिता की अवधारणा मुख्य रूप से आधुनिक राष्ट्र-राज्य की उस सोच से जुड़ी है जिसमें नागरिकों को धर्म के आधार पर अलग-अलग कानूनों के बजाय एक समान कानूनी ढाँचे के अंतर्गत रखा जाता है। समान नागरिक कानून को सामान्यतः नागरिक समानता, लैंगिक न्याय और आधुनिक कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, इसलिए औवेसी का यह कहना कि यूसीसी का विचार किसी धर्म के खिलाफ है, पूरी तरह सही नहीं लगता है।

यूसीसी के समर्थन का एक बड़ा तर्क महिलाओं के अधिकारों से भी जुड़ा है। अलग-अलग पर्सनल लॉ के कारण कई बार महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पाते। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर कई बार अदालतों में बहस हो चुकी है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में यूसीसी पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। अगर एक समान कानून लागू होता है तो इससे महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति के मामलों में अधिक समान अधिकार मिल सकते हैं।

इसी संदर्भ में अक्सर गोवा और उत्तराखण्ड का उदाहरण दिया जाता है, जहां गोवा एवं उत्तराखण्ड सिविल कोड सभी समुदायों पर लगभग समान रूप से लागू होता है, जोकि यह दिखाता है कि भारत में भी समान नागरिक कानून का मॉडल संभव है। देश में यूसीसी को न्याय, समानता और आधुनिक कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लागू किया जाना है, इसलिए इसे लागू होना ही चाहिए।

धूरी में 21.65 करोड़ रुपये की लागत से बने सब-डिविजनल अस्पताल और माता-शिशु स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से संगरूर का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ: भगवंत सिंह मान

मुफ्त इलाज और 10 लाख की स्वास्थ्य योजना के साथ ह्यआपह्न सरकार किसी भी परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहने देगी

सिटी दर्पण संवाददाता
धूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज धूरी में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले सब-डिविजनल अस्पताल और 30 बिस्तरों की क्षमता वाले माता-शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक को लोगों को समर्पित किया। यह परियोजना पंजाब की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और संगरूर जिले में स्वास्थ्य ढांचे को बड़ा बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, यह परियोजना बुनियादी ढांचे को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और डॉक्टरों व स्टाफ की उपलब्धता को बेहतर बनाकर सुलभ एवं मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे न केवल धूरी शहर बल्कि आसपास के लगभग 70 गांवों के लोगों को भी लाभ मिलेगा, जिससे हजारों लोगों को घर के नजदीक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने आगे कहा, 21.65 करोड़ रुपये की लागत से बना यह कॉम्प्लेक्स लगभग 73,000 वर्ग फुट में फैला अत्याधुनिक भवन है, जो इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। इसमें ओपीडी, इनडोर इलाज, इमरजेंसी सेवाएं, जांच सुविधाएं और विशेष सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे सेकेंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के दोहरे ढांचे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 50 बिस्तरों वाला सब-डिविजनल अस्पताल व्यापक सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाएं देगा, जबकि 30 बिस्तरों वाला माता-शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल को और मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया, यह अस्पताल वर्ष 1978 में 30 बिस्तरों के साथ स्थापित हुआ था, बाद में इसे 50 बिस्तरों तक अपग्रेड किया गया और अब इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस 80 बिस्तरों वाला अस्पताल बना दिया गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। बुनियादी सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा, अस्पताल में 13 ओपीडी कमरे, इमरजेंसी ब्लॉक, दो रजिस्ट्रेशन काउंटर और बड़ी व छोटी सर्जरी के लिए 7 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसके अलावा तीन लैबोरेट्री, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा, अस्पताल में 12 निजी कमरे, 6 जनरल वार्ड, एक पूर्ण रूप से कार्यशील दवा भंडार, एसएमओ कार्यालय, 11 नर्स स्टेशन और 2 लिफ्टें हैं, जो मरीजों की बेहतर देखभाल और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करती हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, अस्पताल में सर्जिकल सेवाओं के साथ घुटना प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञ डॉक्टर, विशेषकर कान-नाक-गला (ईएनटी) के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेंगे। माता-शिशु स्वास्थ्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, यह समर्पित केंद्र अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञों की निगरानी में सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी की सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे माताओं और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी।

व्यापक स्वास्थ्य सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने 1500 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की है, जिनमें 600 से ज्यादा विशेषज्ञ और 900 से अधिक जनरल डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी क्लीनिकों में 800 से अधिक डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं बेहतर हुई हैं।

उन्होंने कहा, हमने सेकेंडरी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है और आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क का विस्तार किया है। 300 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद के जरिए मुफ्त दवाइयों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वित्तीय सुरक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को बिना आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज मिल सके।

अंत में उन्होंने कहा, इस परियोजना से धूरी के 58,000 से अधिक निवासियों और आसपास के हजारों लोगों को लाभ होगा। हम पंजाब के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

मलोट को बड़ी राहत: 12 करोड़ की लागत से बना अंडर ब्रिज लोगों को समर्पित: डॉ. बलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/मलोट/श्री मुक्तसर साहिब

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज मलोट में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए अंडर ब्रिज का उद्घाटन करते हुए इसे क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया। यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अंडर ब्रिज मलोट शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, जो यातायात को अधिक सुचारू और तेज बनाते हुए रोजमर्रा की आवाजाही में आने वाली परेशानियों को कम करेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी हद तक कमी आएगी और सड़क हादसों को रोकने में भी मदद मिलेगी। यह अंडर ब्रिज केवल एक ढांचागत परियोजना नहीं, बल्कि मलोट के लोगों के सपनों की साकार तस्वीर है। वर्षों से रेलवे फाटकों के कारण रुकती जिंदगी, देर से पहुंचते छात्र और आपातकालीन सेवाओं में आने वाली बाधाएं अब अतीत की बात बन जाएंगी। यह परियोजना लोगों के दैनिक जीवन को सुगम बनाते हुए क्षेत्र के विकास को नई गति देगी।

उन्होंने शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस अंडर ब्रिज की लंबे समय से चली आ रही मांग आज पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि जो शहर कई दशकों से दो हिस्सों में बंटा हुआ था, अब इस अंडर ब्रिज के माध्यम से उसका समन्वय संभव हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना शहर के विकास को नई दिशा देगी।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और राज्य के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों की अन्य समस्याओं को भी ध्यानपूर्वक सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

शिवालिक किड्स स्कूल, जैतो के विद्यार्थियों ने सिल्वर जोन ओलंपियाड में जीते स्वर्ण पदक

सिटी दर्पण संवाददाता
जैतो

शिवालिक किड्स स्कूल, जैतो के विद्यार्थियों ने सिल्वर जोन ओलंपियाड में हिंदी और विज्ञान विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किए।कक्षा 4 के मोहिक मित्तल, मीनाक्षी शर्मा और नैतिक शर्मा ने शानदार सफलता हासिल की। कक्षा 6 से लीजा, मुस्कान और हरदीप ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कक्षा 7 की सुखरीत कौर और वंशिका ने भी उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की। कक्षा 8 के सरिजा, याशिका, कशिशप्रीत, शिवांजलि और दीपिंदर ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती सुखविंदर कौर ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन श्री गौरव गर्ग, श्रीमती दीपि गर्ग तथा सरदार गुरमेल सिंह ने भी विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। यह उपलब्धि विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता को दशार्ती है।

गैंगस्टरों ते वार का 56वां दिन: पंजाब पुलिस ने 587 स्थानों पर की छापेमारी; 178 गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों के तहत शुरू की गई निर्णायक ह्यगैंगस्टरों ते वारह्न मुहिम के 56वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 587 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि ह्लगैंगस्टरों ते वारह्व पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसे 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

56वें दिन पुलिस टीमों ने 178 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 नुकीले हथियार बरामद किए, जिससे इस अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 15,072 हो गई है। इसके अलावा 99 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 59 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं। इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ह्ल युद्ध नशों विरुद्ध ह्व के 381वें दिन भी जारी रखते हुए आज 69 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 547 ग्राम हेरोइन, 550 ग्राम अफीम, 918 किलोग्राम भूक्की, 544 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1300 रुपये की ड्रग मनी बरामद की।

इसके साथ ही केवल 381 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 53,965 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 58 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया।

मेडिकल कॉलेजों को लेकर बोले गए झूठ पर बलबीर सिंह सिद्धू ने आप सरकार को घेरा

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बदलाव के नारे के साथ सत्ता में आई यह सरकार लोगों से किए गए वादे पूरे करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक जमीन पर एक भी नया मेडिकल कॉलेज बनता नजर नहीं आ रहा।

सिद्धू ने कहा कि हाल ही में विधानसभा में इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने यह कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि 2017 से 2022 के दौरान कांग्रेस सरकार के समय भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। उन्होंने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत और तथ्यों के विपरीत है।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान मोहाली में ऊ१. इ. फ ओुर्ी`१ र३३ी क्ल्ल२३३४३ी ड्ढ टीर्ू ग्रील्लूी२ की स्थापना 2021 में की गई थी, जहां लगभग 100 टइइर सीटें हैं और इस समय करीब 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इस साल यहां से लगभग 100 छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनकर निकलेंगे।

बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि अअढ के मंत्रियों को बिना तथ्यों की जांच किए इस तरह के गलत बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को गुमराह करने के बजाय सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को मोहाली में बने इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिद्धू ने कहा कि यदि सरकार अपने ही राज्य में बनी संस्थाओं से अनजान है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अंत में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल दावों और विज्ञापनों तक ही सीमित रह गई है, जबकि जमीन पर वास्तविक काम कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, जिसका लाभ आज भी पंजाब के लोगों को मिल रहा है।

संक्षिप्त-समाचार

शिरोमणि कमेटी ने ए.आई. टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो का कड़ा नोटिस लिया

जैतो। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब की गरिमा को ठेस पहुंचाने और सिख संगत की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वीडियो बनाने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। जब अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो सामने आए, तो शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इसे गंभीरता से लिया और संबंधित अकाउंट और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल से सिखों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी ऐसे मामलों की गंभीरता को गंभीरता से ले रही है और ए.आई. के क्षेत्र के एक्सपट्र्स की मदद से इसे रोकने की कोशिश कर रही है। एडवोकेट धामी ने कहा कि सचखंड श्री हरमंदिर साहिब सिखों का केंद्रीय स्थान है, जहां से पूरी इंसानियत को भाईचारे का संदेश मिलता है। कुछ लोग इस पवित्र जगह का गलत तरीके से वीडियो बनाकर सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, जिस पर सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा काम न करे। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष ने संगत से भी अपील की कि वे ऐसा कोई वीडियो आगे शेयर न करें, जिससे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने पाम एक्स्पो दिल्ली के लॉन्च की घोषणा की

मोहाली। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने उत्तर भारत के तेजी से विकसित हो रहे प्रो-एवी इकोसिस्टम को देखते हुए पाम एक्स्पो दिल्ली के लॉन्च की घोषणा की है। प्रोफेशनल ऑडियो, विजुअल एवं लाइटिंग टेक्नोलॉजी के लिए भारत के अग्रणी मंच पाम एक्स्पो मुंबई की सफलता के बाद अब राजधानी दिल्ली में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। एक्स्पो का पहला संस्करण 7 से 9 जनवरी 2027 के बीच भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 70 से 100 प्रदर्शकों के शामिल होने और 5,000 से 7,000 उद्योग पेशेवरों के आने की उम्मीद है। इस शो का औपचारिक अनावरण दिल्ली में एक हाई-ऑक्टेन नेटवर्किंग इवनिंग के साथ हुआ, जिसमें उद्योग जगत के दिग्गज, इनोवेटर्स और प्रमुख हितधारक शामिल हुए। लॉन्च के अवसर पर श्री योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने कहा कि आज प्रोफेशनल ऑडियो मार्केट 750 से 850 मिलियन डॉलर के बीच है, और लाइटिंग उद्योग 11 फीसदी सालाना की दर से बढ़ते हुए 2 बिलियन डॉलर पर पहुंचने वाला है। यह क्षेत्र देश के सबसे तेजी से विकसित होते कॉरीडोर्स में से एक है। यहां प्रीमियम ऑडियो के अडॉप्शन की दर राष्ट्रीय औसत से 25 फीसदी अधिक है। 300 से अधिक प्रोफेशनल वैन्यू उत्तर भारत को ऑडियो-विजुअल बदलाव का केन्द्र बिन्दु बनाते हैं। आधुनिक एवं बड़े-पैमाने के समाधानों की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। पाम दिल्ली की अवधारणा उद्योग जगत के ऐसे मंच के रूप में तैयार की गई है, जो मार्केट तक पहुंच बढ़ाकर उद्योग जगत को उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करेगा।

एक्सिस मैक्स लाइफ ने इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी 5.0 के निष्कर्ष जारी किए

चंडीगढ़। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपनी इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी (आइरिस) के पांचवें संस्करण से उत्तर भारत से मिले महत्वपूर्ण निष्कर्ष जारी किए हैं। इस अध्ययन को मार्केटिंग डाटा एवं एनालिटिक्स के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी कंपनी कांतार के साथ मिलकर किया गया है। अध्ययन से मिले निष्कर्ष दिखाते हैं कि उत्तर भारत में रिटायरमेंट की तैयारियों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लगातार जागरूकता और रिटायरमेंट के लिए सतर्कता से इस तैयारी में मदद मिली है। हालांकि अभी भी भावनात्मक एवं वित्तीय पर्याप्तता की चिंताएं लोगों पर हावी हैं। इस अध्ययन में रिटायरमेंट की तैयारियों से संबंधित विभिन्न मानकों पर इस जोन की सतर्कता में लगातार प्रगति की तस्वीर सामने आई है। पिछले पांच साल में उत्तर भारत का रिटायरमेंट इंडेक्स स्कोर सुधरकर 41 से 48 हो गया है। यह पिछले कुछ वर्षों में सार्थक प्रगति को दिखाता है और राष्ट्रीय औसत के अनुरूप है। यह प्रगति विशेषरूप से स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों के मामले में देखने को मिली है। वित्तीय तैयारियों में काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ के डायरेक्टर एवं चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुराग गुप्ता ने कहा कि आइरिस 5.0 से उत्तर भारत को लेकर मिले नतीजे एक ऐसे क्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लोग हेल्थ एवं प्रोटेक्शन को लेकर बहुत सक्रिय हैं।

स्वच्छ घर स्वच्छ भारत पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनजागरूकता

चंडीगढ़। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और थिएटर आट्र्स चंडीगढ़ के सहयोग से नाटक स्वच्छ घर स्वच्छ भारत के द्वारा स्वच्छता की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी मे अहमियत के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया गया तथा यह संदेश दिया गया कि कूड़ा-कर्कट इधर-उधर फैलाने से गंदगी और बीमारियाँ फैलती हैं। नाटक में कलाकारों ने प्रभावशाली ढंग से बताया कि यदि हम अपने घर, गली और आसपास के वातावरण को साफ रखें तो हमारा जीवन स्वस्थ और बेहतर बन सकता है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें और स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग दें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर और आसपास को साफ रखेगा तो हमारा देश भी स्वच्छ और सुंदर बनेगा। इस नाटक का लेखन तथा निदेशन राजीव मेहता ने किया और यह नाटक फ्रेगरेंस गार्डन सेक्टर 36 चंडीगढ़ में किया गया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना और उन्हें स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना था, ताकि स्वच्छ घर झ्र स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके।

संकट से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग

पंजाब में एलपीजी संकट के आसार, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जताई चिंता

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब में एलपीजी आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पंजाब (एफएलडीपी) ने मंगलवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जमीनी हकीकत सामने रखी। फेडरेशन ने सरकार के पर्याप्त आपूर्ति के दावों और जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं व डिस्ट्रीब्यूटर्स को हो रही परेशानियों के बीच बढ़ते अंतर पर गंभीर चिंता व्यक्त की। फेडरेशन के अध्यक्ष गुरपाल सिंह मान ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते जियो-पोलिटिकल तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण सप्लाई मार्गो में रुकावट के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अचानक एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त तैयारी और क्लीयर काम्युनिकेशन के लिए गए इस फैसले से उपभोक्ताओं में घबराहट फैल गई है और संभावित कमी की आशंका बढ़ गई है।

फेडरेशन ने आगे बताया कि स्थिति को संभालने के बजाय हाल के नीतिगत फैसलों ने भ्रम और चिंता को और बढ़ा दिया है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन के बीच ही बुकिंग की अनुमति, साथ ही 3-4 दिनों तक बुकिंग चैनलों का अस्थायी बंद रहना, लंबित बुकिंग्स में भारी वृद्धि का कारण बना है। इस बीच, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर उपभोक्ताओं का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि बॉटलिंग प्लांट्स से आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही है।

फेडरेशन ने जोर देकर कहा कि सरकारी दावों के बावजूद राज्यभर में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बैकलॉग और अनियमित आपूर्ति की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सख्त नीतियां, अचानक मूल्य वृद्धि और सिस्टम में रुकावट ने मिलकर उपभोक्ताओं में घबराहट को बढ़ाया है। इसके साथ ही फेडरेशन ने नीति-निमार्ताओं और जमीनी स्तर के स्टेकहोल्डर्स के बीच पूरी तरह से संवादहीनता (लैक ऑफ डायलॉग्स) पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को न तो निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है और न ही उपभोक्ताओं की वास्तविक समस्याओं को समझने का कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है।

फेडरेशन ने यह भी चिंता जताई कि बढ़ती जन-नाराजगी के कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके कर्मचारियों पर दबाव और जोखिम लगातार बढ़ रहा है, जबकि ये समस्याएं उनके नियंत्रण से बाहर हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए फेडरेशन ने तुरंत और प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की है। फेडरेशन ने सरकार और संबंधित एजेंसियों से अपील की कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और आम जनता के साथ पारदर्शी और नियमित संवाद सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बुकिंग नियमों में सुधार कर भ्रम और असमानता को दूर किया जाए। आपूर्ति बढ़ाने और बॉटलिंग प्लांट्स को पूरी क्षमता से चलाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, 100 फीसदी डायरेक्ट अकाउंट क्रेडिट लागू करने की सिफारिश की गई ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सके।

ईरान की एविन जेल पर इजराइली हमला युद्ध अपराध: संयुक्त राष्ट्र जांच प्रमुख

हवाई हमले में 80 लोगों की हुई थी मौत, जिनमें बच्चा और आठ महिलाएं भी थी

चेतावनी: अमरिका-इजराइल हमलों के बाद ईरान में आंतरिक दमन और बढ़ सकता है

एजेंसी (हि.स.)
जिनेवा

संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र जांच टीम ने कहा है कि 2025 में ईरान की कुख्यात एविन जेल पर किया गया इजराइल का हवाई हमला युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। जांच प्रमुख ने साथ ही चेतावनी दी कि हालिया अमरिका-इजराइल हमलों के बाद ईरान में आंतरिक दमन और बढ़ सकता है।

सारा हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि इजराइल ने 2025 में एविन जेल पर

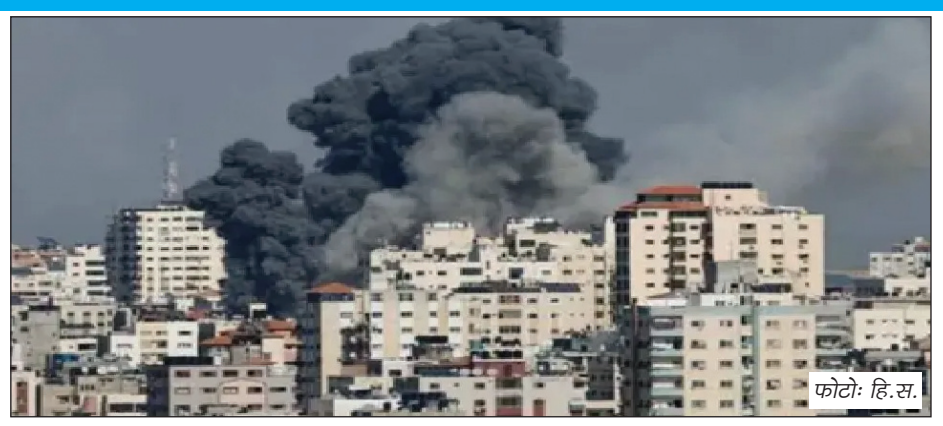
फोटोः हि.स.

हमला कर एक नागरिक संरचना को निशाना बनाया, जो युद्ध अपराध माना जा सकता है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार जून 2025 में तेहरान स्थित एविन जेल पर हुए इस हवाई हमले में 70 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की संख्या करीब 80 थी, जिनमें एक बच्चा और आठ महिलाएं भी शामिल थीं। यह निष्कर्ष पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार, सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर निकाला गया है।

एविन जेल को लंबे समय से राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए जाना जाता है। हालिया अमेरिका-इजराइल हमलों के दौरान भी इस जेल को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं, जिससे वहां बंद कैदियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बताया गया है कि जेल में एक ब्रिटिश दंपती समेत कई विदेशी नागरिक भी बंद हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य मानवाधिकार विशेषज्ञ माई सातो ने भी कैदियों की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किए गए कई लोगों के परिवार अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और जेलों में भोजन व दवाओं की कमी की खबरें मिल रही हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अली बहरीन ने अमेरिका-इजराइल हमलों की निंदा करने की मांग की। उनका कहना है कि इन हमलों में अब तक ईरान में 1,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

इस बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से दूरी बना ली है और जांच से जुड़े सवालों पर उसकी ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में जारी सैन्य कार्रवाई के कारण नागरिकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं।

पश्चिम मेदिनीपुर में उम्मीदवारों की घोषणा से चुनावी हलचल तेज

एजेंसी (हि.स.)
मेदिनीपुर

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद विभिन्न दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और माकपा (सीपीआईएम) ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले की कई महत्वपूर्ण सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।

भाजपा ने दांतन विधानसभा सीट से पार्टी नेता और समाजसेवी अजित कुमार जाना को उम्मीदवार बनाया है। वह लंबे समय से इलाके में भाजपा के सक्रिय नेता के रूप में काम कर रहे हैं और विभिन्न सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है। मोहनपुर समेत दांतन विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों के साथ संपर्क बनाए रखा है। हालांकि वह ज्यादा प्रचार में नहीं रहते, लेकिन क्षेत्र में लोगों के बीच

उनकी अच्छी पहचान मानी जाती है।

वहीं, नारायणगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर रमाप्रसाद गिरि पर भरोसा जताया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इस सीट पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने आगामी चुनाव में फिर से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस बार संगठन को और मजबूत कर बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इधर केशियाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता भद्र हेमरम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। एक समय तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहे भद्र हेमरम अब भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनके नाम की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि भाजपा के इस फैसले से केशियाड़ी में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। दूसरी ओर, नारायणगढ़ विधानसभा सीट से माकपा ने तापस सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के अगले ही दिन पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए उनका नाम घोषित किया। उम्मीदवार घोषित होने के बाद तापस सिन्हा ने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बेलदा शहर में जुलूस भी निकाला। हाथों में लाल झंडे और नारेबाजी के बीच बड़ी संख्या में वाम समर्थक इस रैली में शामिल हुए। तापस सिन्हा लंबे समय से वाम राजनीति से जुड़े हुए हैं और पहले भी विभिन्न चुनावों में पार्टी की ओर से उम्मीदवार रह चुके हैं। हालांकि पिछली बार उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। वाम दलों का कहना है कि आम लोगों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है।

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस पश्चिम एशिया के लिए 44 उड़ानें करेंगी संचालित

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

टाटा की अगुवाई वाली एयरलाइन एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मंगलवार को पश्चिम एशिया क्षेत्र से आने-जाने के लिए 44 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। एयरलाइन ने 'एक्स' पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मिलकर 17 मार्च, 2026 को पश्चिम एशिया क्षेत्र से आने-जाने वाली 44 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। कंपनी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया मस्कट और जेद्दा सहित पश्चिम एशिया से आने-जाने के लिए कुल 44 उड़ानें संचालित करेंगी। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने विदेशी उड़ानों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। इसके परिणामस्वरूप इंडिगो, एयर इंडिया समूह और स्पाइसजेट ने दुबई के लिए अपनी उड़ान सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इंडिगो ने 'एक्स' पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि दुबई हवाई अड्डा अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में मौजूदा हालात को देखते हुए दुबई में विमानों के उतरने की अनुमति अगले आदेश तक रोक दी गई है।

मणिपुर में प्रीपाक, केवाईकेएल एवं केसीपी के 5 उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल। मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के कैडरों के विरूद्ध जारी अभियान के दौरान टेंगनौपाल जिले से अलग-अलग संगठनों के पांच कैडरों को गिरफ्तार किया गया है। उग्रवादियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा आज जारी आधिकारिक सूचना में बताया गया है कि सोमवार को सुरक्षा बलों ने टेंगनौपाल जिले के मोरेह थानांतर्गत अंतरराष्ट्रीय बार्डर पोस्ट (बीपी) 73 और 75 के बीच से वीबीआईजी के पांच कैडरों को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि मोरेह इलाके की सीमा म्यांमार देश से लगती है। गिरफ्तार कैडरों की पहचान वाइखोंग गांव के थांगजम अशोक कुमार सिंह उर्फ खोंगथांग (प्रीपाक), लाइश्रम निपमाचा सिंह उर्फ लोइया (प्रीपाक), थांगजाम मणिमातुम मैतेई उर्फ सना (केवाईकेएल), लाइश्रम इनाओ सिंह उर्फ सनमाचा (केसीपी-एमएफएल) और चिंगंगबाम शक्ति सिंह उर्फ फेयरन (केसीपी-एमएफएल) के रूप में की गयी है।

तमिलनाडु: चुनाव आचार संहिता में एंबुलेंस सेवा पर भी कड़ी निगरानी

एजेंसी (हि.स.)
चेन्नई

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी के तहत 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को भी नियमों के दायरे में लाया गया है। इस संबंध में 108 एंबुलेंस सेवा के राज्य प्रमुख सेल्व कुमार और क्षेत्रीय प्रमुख मोहम्मद बिलाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विस्तृत जानकारी दी है।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने 15 मार्च को आधिकारिक घोषणा की थी और उसी के साथ आचार संहिता लागू हो गई। इसके तहत उम्मीदवारों और आम लोगों के लिए कई नियम लागू किए गए हैं। इनमें 50 हजार रुपये से अधिक नकद ले जाने पर उसके दस्तावेज साथ रखना

फोटोः हि.स.

अनिवार्य है। इसी के चलते अब 108 एंबुलेंस में ले जाए जाने वाले मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को भी अधिक मात्रा में नकद पैसा साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि वे पैसे ले जाते हैं तो उसकी जानकारी संबंधित दस्तावेज में दर्ज की जाएगी। 108 एंबुलेंस कर्मचारियों के लिए नए नियम विधानसभा चुनाव को देखते हुए 108 एंबुलेंस के ड्राइवरों और कर्मचारियों के लिए भी कई नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिसके मुताबिक ड्यूटी के दौरान एंबुलेंस चालक और कर्मचारी किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। वर्तमान में एक निजी हेल्थ सर्विस कंपनी के माध्यम से पूरे तमिलनाडु में लगभग 1,353 एंबुलेंस संचालित की जा रही हैं।

संक्षिप्त-समाचार

नेपाल में आरएसपी के सांसदों के लिए दो दिवसीय संसदीय प्रशिक्षण का आयोजन

काठमांडू। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) ने प्रतिनिधि सभा के अपने नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए मंगलवार से दो दिवसीय संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। आरएसपी के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य सांसदों को संसदीय प्रक्रिया, नीति निर्माण, विधायी प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों की व्यापक जिम्मेदारियों की समग्र समझ प्रदान करना है। आरएसपी के उपाध्यक्ष डीपी अर्याल के अनुसार यह प्रशिक्षण आरएसपी के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वह राष्ट्रीय राजनीति में अपनी बढ़ती भूमिका के अनुरूप एक सक्षम और जानकारीपूर्ण संसदीय टीम तैयार करना चाहती है। पार्टी प्रवक्ता मनीष झा ने बताया कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख हिस्सा संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और अधिकारों पर केंद्रित है। नेपाल सरकार के पूर्व सचिव सुरेश अधिकारी संसद के संचालन, उसकी संस्थागत भूमिका और जिम्मेदारियों पर सत्र लेंगे। इसी तरह पूर्व कानून सचिव तोयनाथ अधिकारी सांसदों को विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें बताया जाएगा कि संघीय संसद में विधेयक कैसे तैयार, बहस और पारित किए जाते हैं। आरएसपी के उपाध्यक्ष डॉ. स्वर्णिम वाग्ले देश की वर्तमान स्थिति, पार्टी की प्रतिबद्धताओं और शासन में सांसदों की अपेक्षित भूमिका पर प्रमुख सत्र प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष डोल प्रसाद अर्याल भी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे, जहां वे चुनाव अभियान के अनुभव साझा करेंगे और पार्टी की संसदीय रणनीति पर मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम में समूह निर्माण गतिविधियां भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सांसदों के बीच समन्वय, टीमवर्क और आंतरिक संचार को मजबूत करना है।

निजी सचिव को एनटीएनसी का अध्यक्ष नियुक्त करने पर प्रधानमंत्री कार्की की आलोचना

काठमांडू। प्रधानमंत्री के निजी सचिव आदर्श श्रेष्ठ को नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन (एनटीएनसी) का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सुशीला कार्की की व्यापक आलोचना शुरू हो गई है। जेन-जी एक्टिविस्ट रक्षा बम ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे 'नैतिकता और विशेषज्ञता का मजाक' बताया है। बम का कहना है कि जैव विविधता और प्रकृति संरक्षण जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना संबंधित विशेषज्ञता वाले व्यक्ति की नियुक्ति से संस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संरक्षण में संचालित नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन एक ऐसी संस्था है, जो केवल प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित है। इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि इतनी महत्वपूर्ण संस्था का नेतृत्व उसी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जिसके पास संबंधित ज्ञान और अनुभव हो। बम ने प्रधानमंत्री पर 'भावनात्मक पक्षपात और भाई-भतीजावाद' का आरोप लगाते हुए कहा कि योग्य विशेषज्ञ की जगह अपने करीबी सहयोगी को नियुक्त करना गलत संदेश देता है। बम ने यह भी स्वीकार किया कि सरकार ने देश को एक कठिन दौर से निकालने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर निर्णय का बिना शर्त समर्थन किया जाए। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री की मंशा और सद्भावना को समझते हैं, लेकिन राज्य पोषित संस्थाओं को योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर चलाया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत नजदीकी या भावनात्मक आधार पर। बम ने यह भी कहा कि भले ही निजी सचिव ने प्रधानमंत्री की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण में इस तरह का पद स्वीकार करना 'अप्राकृतिक और अनैतिक' प्रतीत होता है।

भूमिका श्रेष्ठ बनीं नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद

काठमांडू। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद के रूप में चयनित हुई हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी ने समानुपातिक सूची से चुना है। निर्वाचन आयोग ने सोमवार शाम सूची सार्वजनिक की, जिसमें उनका नाम भी है। हालांकि इससे पहले जब नेपाल ने अपना पहला संविधान सभा का निर्वाचन 2008 में किया था उस समय संविधान सभा में एशिया के पहले समलैंगिक सांसद के रूप में सुनिल बाबु पंत चुने गए थे लेकिन संसद में महिला ट्रांसजेंडर के रूप में भूमिका पहली सांसद बनी हैं। भूमिका स्वयं एक ट्रांसजेंडर महिला हैं। जन्म के समय वह लड़का थीं और उनका नाम कैलाश था। बाद में उन्होंने अपनी भावनाओं के अनुसार अपना रूप और नाम बदला और भूमिका बनीं। भूमिका श्रेष्ठ का जन्म 1987 में काठमांडू के नैकाप में हुआ था। परिवार, स्कूल और समाज में भेदभाव और अपमान के कारण उन्हें कक्षा 9 के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सन 2005 में उन्होंने काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय से 'कैलाश श्रेष्ठ' नाम से नागरिकता प्राप्त की, जिसमें उनका लिंग 'अन्य' उल्लेख किया गया था। नेपाल में तीसरे लिंग को कानूनी मान्यता मिलने के बाद नागरिकता में 'अन्य' लिंग रखने की व्यवस्था शुरू हुई थी। बाद में महिला पहचान के रूप में स्वीकार किए जाने की मांग करते हुए उन्होंने नागरिकता संशोधन के लिए पहल की। लिंग परिवर्तन के प्रमाण के साथ उन्होंने आवेदन दिया।

देशभर में तेजी पकड़ रहा एचपीवी टीकाकरण अभियान, 3 लाख किशोरियों को लगा टीका

नई दिल्ली। देशभर में चल रहे 'मन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान ने तेजी पकड़ ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार अभियान शुरू होने के महज दो सप्ताह के भीतर 14 वर्षीय लगभग 3 लाख किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा और मिजोरम जैसे राज्य इस अभियान में आगे चल रहे हैं। इन राज्यों में स्कूलों और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। एचपीवी वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर से बचाव में अहम भूमिका निभाती है, जो महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसरों में से एक है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि अभियान को लेकर माता-पिता, स्कूलों और समुदायों में जागरूकता बढ़ रही है, जिसके चलते टीकाकरण के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अभियान को शैक्षणिक सत्र के दौरान शुरू किया गया है। कई राज्यों में इस समय परीक्षाएँ चल रही हैं, इसके बावजूद टीकाकरण की रफ्तार बनी हुई है। अधिकारियों ने माना है कि परीक्षा सत्र खत्म होने के बाद अभियान और तेज होगा, जिससे अधिक से अधिक किशोरियों को इसका लाभ मिल सकेगा।

काबुल पर पाकिस्तान के हवाई हमले में कम-से-कम 100 लोगों के मारे जाने का दावा

तालिबान ने कहा- बातचीत खत्म, बदला लेंगे

एजेंसी (हि.स.)
काबुल

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच चल रहे टकराव ने सोमवार रात भीषण रूप ले लिया। पाकिस्तान ने काबुल के एक अस्पताल पर हमला किया जिसमें कम-से-कम १०० लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ताजा हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत और कूटनीति का समय खत्म हो चुका है और अफगानिस्तान इसका बदला लेगा। अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच एक महीने से चल रहे टकराव के बीच स्थितियां तेजी से बिगड़ रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से देर

फोटोः हि.स.

रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाया गया है। हमले में अस्पताल को काफी नुकसान हुआ है। इमारत का ज्यादातर हिस्सा आग लगने के कारण तबाह हो चुका है। बताया जा रहा है कि हमले के समय इस केंद्र पर दो हजार से अधिक लोग मौजूद थे जिसमें कम-से-कम सौ लोगों की जान चली गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं जिनमें कई लोगों को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसे देखते हुए मरने वालों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। पाकिस्तान की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र के अलावा काबुल के कुछ अन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। अफगानिस्तान के मीडिया समूह टोलो न्यूज के मुताबिक, अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात (आईईए) प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने कबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उन उहोने कहा कि इन हमलों के बाद इस्लामाबाद के साथ कूटनीति और बातचीत का समय समाप्त हो गया है, अब बातचीत का रास्ता अपनाने के बजाय हम भी बदला लेने का इरादा रखते हैं।

एरिना न्यूज के मुताबिक मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि जिस अस्पताल में नशा मुक्ति के लिए मरीजों का इलाज चल रहा था, उस पर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर रहे कई लोगों की जान चली गई।

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच यूएई ने संक्षिप्त रूप से हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद फिर खोला

नई दिल्ली/दुबई। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे युद्ध के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मंगलवार को संक्षिप्त रूप से बंद अपना हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया है। दुबई एयरपोर्ट पर लागू प्रतिबंध को हटा लिए गए हैं। इसे फिर संचालन के लिए खोल दिया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी 'डब्ल्यूएएम' ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के हवाले से दी गई जानकारी में बताया कि यह प्रतिबंध हालांकि जल्द ही हटा लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि 'हालात स्थिर' हो गए जिसके कारण उड़ानें फिर से शुरू हो गईं हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब अमीरात की सेना ईरान की ओर से दागे जा रहे ड्रोन और मिसाइल से निपटने का प्रयास कर रही है , इन्हीं प्रयासों के दौरान मंगलवार तड़के दुबई में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद हवाई क्षेत्र को संक्षिप्त रूप से बंद किया गया था, यह प्रतिबंध जल्द ही हटा लिया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने हिमायनी पुरी से जुड़े एपस्टीन फाइल कंटेंट को हटाने का दिया आदेश

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी के जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले भारत में छपे कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस मनी पुष्करणा की बेंच ने कंटेंट हटाने के लिए दायर मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान हिमायनी पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि ये कंटेंट याचिकाकर्ता की छवि को खराब कर रहे हैं, जबकि इन कंटेंट में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने इन कंटेंट को पूरी दुनिया में रोकने की मांग की। मेटा की ओर से पेश वकील अरविंद दातार ने कोर्ट से कहा कि वो पूरी दुनिया में इन कंटेंट पर रोकने का आदेश पारित नहीं करे। पूरी दुनिया में रोक पर एक याचिका उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में लंबित है। भारत पूरी दुनिया में कंटेंट नहीं रोक सकता। इंग्लैंड भी नहीं रोक सकता है। तब जेठमलानी ने कहा

कि कानून ये है कि अगर भारत के कंप्यूटर से कोई कंटेंट अपलोड किया जाता है, तो इसे पूरी दुनिया में रोका जा सकता है। तब दातार ने कहा कि अगर अपलोड करने वाला इसे हटाता है तो ये पूरी दुनिया में हट जाएगा। दातार ने कहा कि दूसरे उच्च न्यायालय भी यही आदेश दे रहे हैं कि इसे भारत में ही रोका जाए। सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से पेश वकील ने भी इसमें हामी भरी। दातार ने कहा कि हिमायनी पुरी अमेरिकी नागरिक हैं। वे अमेरिका में भी याचिका दायर कर पूरी दुनिया में रोक लगाने के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। उसके बाद कोर्ट ने हिमायनी पुरी का संबंध जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले कंटेंट को भारत से हटाने का आदेश दिया।

गुवाहाटी समेत असम के कई इलाकों में तूफान का कहर, घरों की छतें उड़ीं

एजेंसी (हि.स.)
गुवाहाटी

असम की राजधानी गुवाहाटी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सोमवार रात आए तेज तूफान, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। तूफानी हवाओं के कारण कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, वहीं बड़े-बड़े पेड़ों के गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ। अनेक घरों की टीन निर्मित छतें उड़ गईं और झोपड़ीनुमा मकानों को भारी नुकसान पहुंचा।

कामरूप (ग्रामीण) जिले के बोको क्षेत्र में तूफान ने 30 से अधिक गांवों को प्रभावित किया। तेज हवाओं ने घरों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन से लोग संभल भी नहीं पाए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भेहुआ गांव में एक व्यक्ति के तीन घर पूरी तरह से ढह गए, लेकिन परिवार के सदस्य सुरक्षित बच निकले। तूफान का

असर छोटे व्यवसायों पर भी पड़ा है। एक राशन दुकान की टीन की छत तेज हवाओं में उड़ गई, जिससे वहां रखा सामान खराब हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, तूफान के दौरान घरों का सामान, मवेशियों के रहने के स्थान और गोदामों में रखा सामान बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत, अस्थायी आश्रय, बिजली व्यवस्था की मरम्मत और नुकसान के मुआवजे की मांग की है। फिलहाल नुकसान का आधिकारिक आकलन नहीं किया गया है। वहीं पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के खेरनी इलाके में भी तूफान और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। जिरिम कार्बी, जिरिबासा, गोहाईं और दीथलेम गांवों में खासकर सुपारी (तामुल) और नारियल के पेड़ जड़ से उखड़ गए।

निरीक्षण | **डीपीए के चेयरमैन ने मिड सी का दौरा किया**

होर्मुज से 47 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वडीनार पोर्ट पहुंचा 'नंदा देवी'

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

देश में एलपीजी की किल्लत के बीच शिवालिक के बाद अब एलपीजी टैंकर 'नंदा देवी' 47 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर पहुंच गया है। इस समय नंदा देवी से एलपीजी को दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जा रहा है।

गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए) के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह ने मंगलवार को वडीनार टर्मिनल के पास स्थित मिड सी का दौरा किया। यहां मंगलवार को पहुंचे एलपीजी कैरियर नंदा देवी जहाज नंदा देवी के कैप्टन और क्रू-मेंबर से बातचीत की। मिड सी में ही नंदा देवी से पूरी 47 हजार मीट्रिक टन एलपीजी को दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जाएगा। यह काम पूरा

फोटोः हि.स.

होने के बाद एलपीजी का आधा स्टॉक एन्नोर बंदरगाह में ऑफलोड किया जाएगा। इसके साथ ही आधा स्टॉक पश्चिम बंगाल के हल्दीया बंदरगाह पर ऑफलोड होगा। मुंद्रा बंदरगाह पर खड़ा शिवालिक एलपीजी कैरियर अब मुंद्रा में 12 हजार टन एलपीजी का स्टॉक ऑफलोड करके वडीनार मिड सी में जाएगा और शाम को बाकी का बचा स्टॉक बीच समुद्र में दूसरे शिप में ट्रांसफर करेगा, जो बाद में उस स्टॉक को गुजरात के भरूच जिले में खंभात की खाड़ी में स्थित दाहेज बंदरगाह पर और मैंगलोर के दो अलग-अलग टर्मिनल्स पर ऑफ लोड करेगा।

केकेआर को झटका: घुटने की चोट के चलते अधिकतर मैचों से बाहर रहेंगे हर्षित राणा

हर्षित राणा चोटिल, मुस्तफिजुर बाहर; अब जिम्बाब्वे के मुजरबानी पर टिकी उम्मीद

- 29 मार्च को मुंबई इंडियंस से होगा पहला महामुकाबला

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के आगाज से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की गंभीर चोट और उसके बाद हुई सर्जरी के कारण इस साल के आईपीएल के अधिकांश हिस्से से बाहर रह सकते हैं। केकेआर, जो पहले से ही अपने कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धता को लेकर असमंजस में है, उसके लिए राणा का बाहर होना एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है।

सूत्रों और 'ईएसपीएन क्रिकइन्फो' की रिपोर्ट के अनुसार, हर्षित राणा पिछले महीने अपने घुटने की सर्जरी करा चुके हैं। फिलहाल वह बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में 'रिहैबिलिटेशन' (पुनर्वास) प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मेडिकल टीम उनकी रिकवरी पर बारीकी से नजर रख रही है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक उनकी मैदान पर वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख या 'डेडलाइन' तय नहीं की है, जिससे यह स्पष्ट है कि वह टूर्नामेंट के शुरूआती और मध्य चरण के मैचों में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हर्षित राणा की चोट का सिलसिला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के टी20 विश्व कप अभ्यास मैच के दौरान शुरू हुआ था। उस मैच में केवल एक ओवर फेंकने के बाद राणा को घुटने में तेज दर्द महसूस हुआ और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। जांच के बाद सर्जरी को अनिवार्य बताया गया, जिसके कारण वह टी20 विश्व कप से भी बाहर हो गए थे। उनकी अनुपस्थिति में मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम में जगह दी गई थी। विडंबना यह है कि एक ओर जहां हर्षित राणा चोट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके शानदार प्रदर्शन को मान्यता भी मिल रही है। हाल ही में आयोजित 'नमन' पुरस्कार समारोह में उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ उदीयमान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी' के सम्मान से नवाजा गया। उनकी धारदार गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता ने उन्हें केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण का मुख्य स्तंभ बनाया था, जिसकी कमी अब टीम को खलेगी।

केकेआर के लिए मुश्किलें केवल हर्षित राणा तक सीमित नहीं

मथीशा पथिराना: श्रीलंका के घातक गेंदबाज पथिराना भी टी20 विश्व कप के दौरान लगी पिंडली की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं। उनका शुरूआती एकादश में खेलना अभी संदिग्ध है।

मुस्तफिजुर रहमान का न होना: भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षा कारणों के चलते, बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान की भागीदारी पर रोक लगा दी है। केकेआर को इस अनुभवी बाएं हाथ के गेंदबाज के बिना ही मैदान पर उतरना होगा।

ब्लेसिंग मुजरबानी: एक नई उम्मीद -मुस्तफिजुर की जगह की भरपाई के लिए केकेआर मैनेजमेंट ने जिम्बाब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ अनुबंध किया है। मुजरबानी ने आईपीएल को प्राथमिकता देते हुए पाकिस्तान सुपर लीग और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अपना अनुबंध बीच में ही तोड़ दिया है। उनकी उछाल और गति मुंबई की पिचों पर प्रभावी साबित हो सकती है।

अभ्यास सत्र और आगामी रणनीति

कोलकाता नाइट राइडर्स का अभ्यास सत्र इसी बुधवार से शुरू होने जा रहा है। टीम के मुख्य कोच और कप्तान को अब अपनी गेंदबाजी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। केकेआर का पहला मुकाबला 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ होना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि हर्षित राणा की अनुपस्थिति में टीम प्रबंधन किस घरेलू गेंदबाज पर भरोसा जताता है।

पांचवें पीएसपीबी बाबा दीप सिंह हॉकी टूर्नामेंट का दमदार आगाज

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

- खालसा, किरोड़ी मल और विवेकानंद कॉलेज की शानदार जीत

पांचवें पीएसपीबी बाबा दीप सिंह हॉकी (पुरुष एवं महिला) टूर्नामेंट का आगाज मंगलवार को मेजबान श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के मैदान पर शानदार मुकाबलों के साथ हुआ। पहले दिन पुरुष वर्ग में खालसा कॉलेज और किरोड़ी मल कॉलेज, जबकि महिला वर्ग में विवेकानंद कॉलेज ने प्रभावशाली जीत दर्ज की।

पुरुष वर्ग के मुकाबले में श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज ने इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान (आईजीआईपीईएस) को 6-0 के बड़े अंतर से पराजित किया। खालसा कॉलेज की जीत के नायक रहे विपिन, जिन्होंने चार गोल दागे, जबकि मनीष और तनुज ने एक-एक गोल का योगदान दिया। शानदार प्रदर्शन के लिए विपिन को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। एक अन्य मुकाबले में किरोड़ी मल कॉलेज ने सेंट स्टीफंस कॉलेज पर 11-2 की एकतरफा जीत दर्ज की। इस मैच में समर सिंह और रोहित डांगी ने चार-चार गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए समर सिंह को 'मैन ऑफ द मैच' से नवाजा गया। महिला वर्ग के मुकाबले में विवेकानंद कॉलेज ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज को कड़े संघर्ष में 1-0 से हराया। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल महिमा ने 58वें मिनट में किया। हालांकि, सराहनीय प्रदर्शन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की मोनिका को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह में पीएसपीबी के सलाहकार श्री ललित वत्स मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सरिता त्यागी विशिष्ट अतिथि रहीं।

उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने अनुभव साझा किए। टूर्नामेंट का उद्घाटन एसजीटीबी खालसा कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर गुरमोहिंदर सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिषद के सहायक निदेशक डॉ. सुशील कुमार तथा पद्मश्री सम्मानित डॉ. रविचतुर्वेदी की उपस्थिति में किया गया। गौरतलब है कि टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण 'द कम्प्लीट सॉल्यूशंस स्पोर्ट्स' प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 से बाहर हुए बेवन जैकब्स, कवर के तौर पर कटेने क्लार्क शामिल

एजेंसी (हि.स.)
हैमिल्टन

फोटोः हि.स.

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बेवन जैकब्स घुटने की चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अनकैप्ड खिलाड़ी कटेने क्लार्क को टीम में कवर के तौर पर शामिल किया गया है।

23 वर्षीय जैकब्स को पहला टी20 खेलते समय माउंट माउंगानुई में फील्डिंग के दौरान बाएं घुटने में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। स्कैन में उनके घुटने के किनारे बोन ब्रूज़िंग (हड्डी में चोट) की पुष्टि हुई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि उनकी वापसी को लेकर आगे और जांच की जाएगी। वहीं 26 वर्षीय कटेने क्लार्क हाल ही में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की सुपर स्मैश खिताबी जीत में शानदार फॉर्म में नजर आए थे। उन्होंने टूर्नामेंट में 9 पारियों में 431 रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 61.57 और स्ट्राइक रेट 171.71 रहा। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला मंगलवार, 17 मार्च को हैमिल्टन में खेला जाएगा। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने सात विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बना ली है।

डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों को प्रमुख प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोक सकता है वाडा

एजेंसी (हि.स.)
न्यूयॉर्क

यह सुनने में भले अजीब सा लगे लेकिन विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी (वाडा) एक ऐसा नियम लागू करने पर विचार कर रही है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सभी अमेरिकी सरकारी अधिकारियों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोक सकता है, भले ही उनका आयोजन अमेरिकी धरती पर ही क्यों न हो। अमेरिका में अगले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। इनमें इस साल होने वाला फुटबॉल विश्व कप, 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक खेल और 2034 में यूटा में होने वाले शीतकालीन खेल भी शामिल हैं।

यह लड़ाई ट्रंप की मर्जी से नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि खुद वाडा इसमें अहम भूमिका निभा रहा है जो पिछले एक दशक में अधिकतर समय ट्रंप और बाइडेन प्रशासन तथा अमेरिका की डोपिंग रोधी एजेंसी के रवैए से खुश नहीं है। यह प्रस्ताव मंगलवार को वाडा की कार्यकारी समिति की बैठक के एजेंडे में शामिल है जो इन सभी पक्षों के बीच वर्षों से चल रही बयानबाजी, चेतावनी और संघर्ष में नवीनतम और सबसे चरम कदम है। इसका मूल आधार अमेरिकी सरकार का वाडा के वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करना है। अमेरिका ने 2024 और 2025 के दौरान वाडा के कई मामलों से निपटने के तरीके के विरोध में कुल 73 लाख डॉलर का भुगतान रोक रखा है। इनमें सबसे ताजा मामला चीनी तैराकों से जुड़ा है जिन्हें प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। वाडा ने चीन की संबंधित संस्थाओं की इस बात पर भरोसा किया कि खिलाड़ियों ने गलती से यह पदार्थ ले लिए थे। वाडा के प्रवक्ता जेम्स फिट्जगेराल्ड ने कहा कि यदि यह नियम पारित हो जाता है, तो इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए विश्व कप, लॉस एंजिलिस ओलंपिक और साउथ कैरोलिना में होने वाले शीतकालीन खेल इसके दायरे में नहीं आएंगे। एसोसिएटेड प्रेस के पास इस प्रस्ताव की एक प्रति है जिसमें इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है।

वाडा को ट्रंप पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसने दिया

ओलंपिक और विश्व कप जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीमें भेजने के लिए इसमें शामिल सभी लोगों को वाडा के नियमों का पालन करने की शपथ लेनी होती है। फिर चाहे वे नियम सीधे डोपिंग से संबंधित हों या प्रशासनिक मुद्दों से, जैसा कि इस प्रस्ताव में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के साथ हुए समझौते के तहत सरकारों को वाडा के नियमों का पालन करना होता है। विभिन्न खेल संगठनों की तरह यूनेस्को के साथ हुए समझौते में सरकारों को शुल्क का भुगतान करने और वाडा के नियमों का पालन करने की सहमति शामिल है। बाइडेन प्रशासन में डोपिंग मामलों के प्रमुख रहे राहुल गुप्ता और उनकी उत्तराधिकारी सारा कार्टर ने इसे 'हास्यास्पद' करार दिया। गुप्ता ने कहा, यह सरकार की जिम्मेदारी है, वाडा की नहीं। यह स्पष्ट है कि वाडा का किसी भी नियम आधारित प्रणाली को बढ़ावा देने का प्रयास है जो किसी सरकार, विशेषकर मेजबान सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करता है। यह किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होगा।

विश्व कप से पहले मैत्री मैचों के लिए नेमार ब्राजील की फुटबॉल टीम से बाहर

एजेंसी (हि.स.)
रियो डी जनेरियो

स्टार स्ट्राइकर नेमार को इस महीने अमेरिका में होने वाले मैत्री मैचों के लिए ब्राजील की फुटबॉल टीम में नहीं चुना गया है जिससे उनके विश्व कप में खेलने को लेकर संदेह पैदा हो गया है। ब्राजील के पूर्व कप्तान 34 वर्षीय नेमार अक्टूबर 2023 में चोटिल होने के बाद से पूर्ण फिटनेस हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्राजील 26 मार्च को बोस्टन में फ्रांस के खिलाफ और चार दिन बाद ऑरलैंडो में क्रोएशिया के खिलाफ मैत्री मैच खेलेगा।

ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने सोमवार को कहा, यह एक ऐसी टीम है जिसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो पूरी तरह से फिट हैं। ब्राजीली लीग में सैंटोस और कोरिंथियंस के बीच 1-1 से ड्रॉ रहे मैच में नेमार का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। नेमार ने साओ पाउलो में एक कार्यक्रम में मीडिया से कहा कि दो मैत्री मैचों के लिए ब्राजील की टीम में शामिल न होने से वह दुखी और निराश हैं लेकिन उन्हें अभी उम्मीद है कि वह विश्व कप के लिए टीम में जगह बनाने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा, मेरा पूरा ध्यान हर अभ्यास सत्र और हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करने पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। अभी अंतिम टीम का चयन होना बाकी है। विश्व कप टीम की घोषणा 18 मई को की जाएगी। टीम का आखिरी अभ्यास मैच 31 मई को रियो डी जनेरियो में पनामा के खिलाफ होगा।

विश्व पुनर्चक्रण दिवसः प्रकृति के कर्ज को उतारने का एक संकल्प

हर साल, पृथ्वी अपने प्राकृतिक संसाधनों के अरबों टन को मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित करती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप इसका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम सभी अपने स्तर पर योगदान दें और कचरे को कम करने, वस्तुओं के पुनः उपयोग और पर्यावरण के पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित करें। पर्यावरण और पृथ्वी की देखभाल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका पुनर्चक्रण है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हमें यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि पुनर्चक्रण हमारी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा है। इस दिन का उद्देश्य लोगों, संगठनों, कंपनियों और सरकारों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके।

मुख्य उद्देश्य

इस दिवस को मनाने के पीछे कई गंभीर और दूरगामी उद्देश्य छिपे हैं- **छठे संसाधन की पहचानः** दुनिया के पास पांच मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं-पानी, हवा, तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला। पुनर्चक्रण को 'छठा संसाधन' घोषित करना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। **जागरूकता फैलानाः** लोगों को यह समझाना कि पुनर्चक्रण केवल विशेषज्ञों का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। **नीति निमार्णः** विश्व के नेताओं और सरकारों को पुनर्चक्रण के अनुकूल नीतियां बनाने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। **प्रदूषण नियंत्रणः** प्लास्टिक, ई-वेस्ट और औद्योगिक कचरे से होने वाले जल और वायु प्रदूषण को रोकना।

पुनर्चक्रण का महत्व

पुनर्चक्रण आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है- **प्राकृतिक संसाधनों की बचतः** उदाहरण के लिए, 1 टन रिसाइकिल कागज बचाने से लगभग 17 पेड़ और 7,000 गैलन पानी की बचत होती है। **ऊर्जा संरक्षणः** नई वस्तुओं को बनाने की तुलना में पुरानी वस्तुओं को रीसायकल करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। एल्युमिनियम को रीसायकल करने में नई धातु बनाने की तुलना में 95% कम ऊर्जा खर्च होती है। **कार्बन उत्सर्जन में कमीः** ग्लोबल रिसाइक्लिंग फाउंडेशन के अनुसार, पुनर्चक्रण के माध्यम से हर साल लगभग 700 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जो जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करता है। **आर्थिक लाभः** रीसाइक्लिंग उद्योग दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार देता है और वैश्विक जीडीपी में अरबों डॉलर का योगदान देता है।

कचरा प्रबंधन की चुनौतियाँ और समाधान

आज भी दुनिया का केवल एक छोटा हिस्सा ही सही तरीके से रीसायकल हो पाता है। **चुनौतीः** कचरे का सही वर्गीकरण न होना, प्लास्टिक की बढ़ती खपत और ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) का अंबार। **समाधानः** हमें 'सर्कुलर इकोनॉमी' को अपनाना होगा, जहाँ वस्तुएं उपयोग के बाद कचरा नहीं बनतीं, बल्कि फिर से उत्पादन चक्र में लौट आती हैं।

वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का इतिहास

वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस की शुरूआत 2015 में हुई थी, जब ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइक्लिंग के अध्यक्ष रणजीत एस. बक्सी ने इसे वर्ल्ड पुनर्चक्रण कन्वेंशन में पेश किया। हालाँकि, इस दिवस को पहली बार 2018 में आधिकारिक रूप से मनाया गया। 18 मार्च को यह दिन मनाने का निर्णय BIR की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लिया गया। यह दिन वैश्विक पुनर्चक्रण फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में पुनर्चक्रण उद्योग को समर्थन और बढ़ावा देने का कार्य करता है। इस दिन का उद्देश्य 'पुनर्चक्रण हीरोज' को सम्मानित करना और 'अपशिष्ट' को 'संसाधन' के रूप में देखने की सोच को विकसित करना है। अब हर साल, यह दिवस केवल कचरा कम करने की याद दिलाने के लिए ही नहीं, बल्कि सरकारों और कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए भी मनाया जाता है ताकि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस पर हम क्या क्या कर सकते हैं

यह समय है कि हम सभी एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश करें। आप भी इस दिन को सार्थक बनाने के लिए निम्नलिखित तरीकों अपना सकते हैंः **वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस के कार्यक्रमों में भाग लेंः** हर साल इस दिन कई समुदाय और शहर एकजुट होकर पृथ्वी को बचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अपने शहर या नगर पालिका से संपर्क करें और पता करें कि इस वर्ष कौन-कौन से कार्यक्रम और पुनर्चक्रण अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई आयोजन नहीं हो रहा है, तो स्वयं एक कार्यक्रम आयोजित करने की पहल करें। स्थानीय संगठनों, स्कूलों, चर्चों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाएं और पुनर्चक्रण को एक आदत बनाएं। **पुनः उपयोग को प्राथमिकता दें-** किसी वस्तु को कचरे में फेंकने से पहले सोचें कि क्या इसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है? उदाहरण के लिएः प्लास्टिक बैग या ज़िपर बैग को धोकर दोबारा इस्तेमाल करें। सुपरमार्केट से लाए गए प्लास्टिक कंटेनरों को बच्चों के लंच बॉक्स में उपयोग करें। एल्युमिनियम फॉयल को दोबारा इस्तेमाल करें। अगर किसी चीज को सिर्फ दो बार उपयोग किया जाए, तो उसका अपशिष्ट आधा हो सकता है! **पुनर्चक्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाएं-** वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस अभी नया है और इसे अधिक पहचान दिलाने की आवश्यकता है। खासकर जब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 15 वर्षों में वैश्विक कचरा दोगुना हो जाएगा।

किन-किन चीजों को किया जा सकता है रिसाइकल

चीजों को इस्तेमाल करते हुए हमेशा तीन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। रिड्यूस यानी चीजों को खरीदने की दर कम करना, रियूज यानी जो चीजें दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना और रिसाइकिल यानी इन्हें किसी नई तरह से इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाना, जैसे पुराने अखबार से लिफाफे तैयार किए जाते हैं या पुराने प्लास्टिक के बर्तनों में लोग पौधे लगा देते हैं।

पीजीआई चंडीगढ़ में राजभाषा समारोह का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में राजभाषा समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उपस्थित अधिकारियों एवं कार्मिकों को भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं संस्थान में उसके कार्यान्वयन के बारे में अवगत कराया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के संकायाध्यक्ष (अनुसंधान) प्रो. संजय जैन ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि भारत देश अनेकता में एकता की एक ऐसी मिसाल है जिसमें अनेक जातियां, संस्कृति, भाषाएं और बोलियां हैं। विवधताओं से भरे देश में राजभाषा हिन्दी देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी मातृभाषा में सोचें एवं काम करें। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम लोगों को स्वस्थ रखने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंदी हमारे लिए केवल एक दायित्व नहीं है बल्कि यह देश की धड़कन से जुड़ने का एक सुगम और सरल माध्यम भी है। अतः चिकित्सा संस्थान में कार्य करने के नाते हमारी हिन्दी में काम करने के प्रति जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि हमारा सीधा सम्पर्क आम लोगों, जो इलाज करवाने के लिए हमारे संस्थान में आते हैं तथा रोग से भयभीत होते हैं, के साथ होता है। यदि हम उनसे हिन्दी में बात कर उन्हें उनके रोग के बारे में समझाते हैं तो उनका तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। यही नहीं, संस्थान का कामकाज जितना हम हिन्दी में करेंगे उतनी ही हमारी परेशानी कम होगी और जनता एवं प्रशासन के बीच की दूरी उतनी ही घटेगी। पुरस्कृत कार्मिकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सभी राजभाषा अधिनियमों, नियमों तथा इनके संबंध में समय-समय पर लिए गए निर्णयों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थान में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से किया जा रहा है, किन्तु राजभाषा संबंधी निदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। डॉ. विपिन कौशल, चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने उपस्थित कार्मिकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमारे संस्थान में कार्यरत अधिकांश कार्मिक हिंदी का अपेक्षित ज्ञान अथवा हिन्दी टाइपिंग की जानकारी रखते हैं तथा उनको हिन्दी में कार्य करने के लिए शब्दकोश, तकनीकी शब्दावलियां एवं कार्यालयी प्रयोग से जुड़ी सामग्री वितरित की हुई हैं। संस्थान के सभी कंप्यूटरों में हिन्दी टाइपिंग की सुविधा के लिए हिन्दी फोण्ट उपलब्ध है। उन्हें संस्थान की वैबसाइट से डाउनलोड कर कंप्यूटरों में अपलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने संस्थान के सभी डॉक्टरों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से राजभाषा हिन्दी के विकास और समृद्धि को राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए अपील की कि वे दैनिक कामकाज और व्यवहार में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को कारगर बनाने में अपना सहयोग एवं योगदान दें। उन्होनें यह भी कहा कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में यदि कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं तो उनका समाधान संयम और आपसी सहयोग से किया जाए।

इस अवसर पर श्री अनीशलाल एस.वी., नर्सिंग अधिकारी की हिंदी में लिखित पुस्तक नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के देखभालकताओं के लिए होम केयर पैकेज का लोकार्पण किया गया तथा राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए संस्थान में लागू प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत डॉ. रजनी शर्मा, खेल चिकित्सक, श्री नरेंद्र प्रार्थी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (परिवहन), श्री संजय कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, श्री राजेश सक्सैना, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक तथा श्री अभिजीत सिंह, वरिष्ठ फोटोग्राफर को सम्मानित और हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रो. संजय भदादा, नोडल अधिकारी (राजभाषा) ने उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कार्मिकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी जहाँ भी जिस भी पद पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए आत्मीयता से राजभाषा हिंदी का प्रयोग करेंगे और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे तथा अन्य कार्मिकों को भी राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करेंगे।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर: सतपाल शर्मा

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को बैंकों के माध्यम से मिलेगी 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वर्ष जिला पंचकूला के लिए 40 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, जो हरियाणा की निवासी महिला उद्यमी हैं तथा ऋण के लिए आवेदन के समय जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदक पूर्व में लिए गए किसी भी ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत डेयरी, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के अंतर्गत ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के अंतर्गत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ व आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट निर्माण, हैंडलूम, बैग निर्माण, कैंटीन सर्विस आदि शामिल हैं, जिनके माध्यम से महिलाएँ अपना स्वयं का कार्य शुरू कर सकती हैं।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्डध्परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय, जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा नं. 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला दूरभाष नंबर- 0172-2585271 पर संपर्क किया जा सकता है।

श्रीमती अरुणा आसिफ अली राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालका में एल्युमिनी मीट मिलाप 2026 का सफल आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला/कालका

श्रीमती अरुणा आसिफ अली राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालका की प्राचार्या डॉक्टर गीता सुखीजा के कुशल नेतृत्व में एल्युमिनी मीट मिलाप 2026 का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कार्यक्रम एल्युमिनी मीट की प्रभारी डॉक्टर मीनू ख्यालिया और सदस्य डॉ गीतांजलि, डॉक्टर नीरू, डॉ गीता, डॉ नवनीत नैंसी, डॉक्टर सविता, असिस्टेंट प्रोफेसर सोनू, डॉक्टर शबनम और डॉ नमिता के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में किया गया।

प्राचार्या डॉक्टर गीता सुखीजा ने सभी पूर्व विद्यार्थियों का स्वागत किया और अपने संबोधन में कहा कि कॉलेज हमेशा अपने पूर्व विद्यार्थियों को याद करता रहेगा तथा यह आशा भी व्यक्त की सभी पूर्व विद्यार्थी तन व मन से सहयोग करते रहेंगे। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना के साथ किया गया। संगीत विभाग अध्यक्षा डॉक्टर भैरवी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में विभिन्न विद्यार्थियों ने नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया। एम.ए. प्रथम वर्ष के छात्र रवि ने गीत गायन किया। बीए तृतीय वर्ष के छात्र शुभम ने वादन यंत्र बजाया। कीर्ति, रिया, महक, स्नेहा और ध्वनि ने गिद्दा नृत्य की शानदार प्रस्तुति की। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों, विभिन्न शहरों से और विभिन्न बैचों के पुराने छात्र-छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपने छात्र जीवन की यादों को ताजा किया।

पीजीआई में सर्जनों के लिए व्यापक ट्रॉमा प्रबंधन पाठ्यक्रम 2026 का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

जनरल सर्जरी विभाग, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ द्वारा 13-14 मार्च 2026 को सर्जनों के लिए व्यापक ट्रॉमा प्रबंधन पाठ्यक्रम 2026 का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ट्रॉमा केयर एंड बर्न्स एवं इट) के सहयोग से आयोजित किया गया। दो दिवसीय इस शैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य ट्रॉमा देखभाल में कार्यरत सर्जनों के कौशल और ज्ञान को सुदृढ़ करना था। इस पाठ्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता कैडावेरिक वर्कशॉप रही, जिसमें डैमेज कंट्रोल सर्जरी तथा डिफिनिटिव ट्रॉमा सर्जरी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इससे प्रतिभागियों को गंभीर रूप से घायल मरीजों के प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण शल्य कौशल सीखने का अवसर मिला। कार्यक्रम में 'बैटलफील्ड से सीख' विषय पर सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें सशस्त्र बलों के चिकित्सकों ने युद्धकालीन ट्रॉमा देखभाल के अपने अनुभव साझा किए तथा उनकी नागरिक ट्रॉमा प्रबंधन में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। पॉलीट्रॉमा प्रबंधन पर आधारित इंटरएक्टिव केस-आधारित चचाओं ने भी शिक्षण अनुभव को और समृद्ध बनाया। कार्यक्रम में योगदान देने वाले सशस्त्र बलों के विशिष्ट संकाय सदस्यों में ब्रिगेडियर पल्लब चटर्जी, कर्नल जी. पी. रेड्डी, कर्नल रविकांत, कर्नल रोहित मेहरा, कर्नल अजय शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर विशेष वशिष्ठ, लेफ्टिनेंट कर्नल रूपायन भट्टाचार्य और स्क्वाड्रन लीडर विशेष वशिष्ठ शामिल थे। यह कार्यक्रम जेपीएनए ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ तथा सशस्त्र बलों की त्रि-सेवाओं के संकाय के बीच एक अद्वितीय सहयोग का उदाहरण रहा, जिसने नागरिक और रक्षा चिकित्सा क्षेत्रों के बीच आपसी सीख को बढ़ावा दिया। इस आयोजन को पीजीआईएमईआर के निदेशक प्रो. विवेक लाल तथा प्रो. अतुल पराशर, नोडल अधिकारी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ट्रॉमा एवं बर्न्स), एवं इक और प्रो. अंजलि अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ का सहयोग प्राप्त हुआ।

संक्षिप्त-समाचार

आय को लेकर राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण का डाटा एकत्र किया गया

चंडीगढ़। भारत सरकार समय-समय पर व्यक्तियों, परिवारों और प्रतिष्ठानों के मालिकों से जानकारी एकत्र करती है। इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर योजना और नीति निर्माण के लिए किया जाता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसओ का फील्ड ऑपरेशन डिवीजन भारत सरकार के तहत सबसे बड़ा डेटा संग्रह निकाय है और सत्तर से अधिक वर्षों से राज्य सरकारों के साथ मिलकर डेटा संग्रह में लगा हुआ है। अपने अगले दौर (अप्रैल 2026 से मार्च 2026) के दौरान, एनएसओ 'राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण' पर चयनित परिवारों से डेटा एकत्र करेगा। (एन.एच.आई.एस) लोगों की जीवन स्थितियों और आय के पैटर्न के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आर्थिक विश्लेषकों और नीति निमार्ताओं ने आय वितरण पर जानकारी संकलित करने के तीन मुख्य उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य यह समझने की इच्छा से प्रेरित है कि आय वितरण का पैटर्न आर्थिक गतिविधि के पैटर्न, श्रम, पूंजी और भूमि पर प्रतिफल और समाजों के संगठन के तरीके से कैसे संबंधित हो सकता है। दूसरा उद्देश्य नीति निमार्ताओं की इस चिंता को दशार्ता है कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों पर सार्वभौमिक और सामाजिक रूप से लक्षित कार्यों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाए और उनके प्रभाव का आकलन किया जाए। तीसरा उद्देश्य इस बात में रुचि है कि आय वितरण के विभिन्न पैटर्न घरेलू कल्याण और लोगों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। घरेलू आय सर्वेक्षण में एकत्रित जानकारी का उपयोग मुख्य रूप से यह जानने के लिए किया जाएगा कि आय का वितरण जनसंख्या के विभिन्न वर्गों और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कैसे होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली (एनएचआईएस) से प्राप्त आय के अनुमानों से संबंधित आंकड़े, व्यक्तिगत आय की तुलना करने और आय सृजन के स्रोतों और पैटर्न का विश्लेषण करने में सहायक होंगे। यह सर्वे पूरे इंडियन यूनियन को कवर करेगा, सिवाय अंडमान और निकोबार आइलैंड के कुछ गांवों के, जहां पूरे साल पहुंचा नहीं जा सकता। श्री दीपक मैहरा, उप महानिदेशक, एनएसओ, चंडीगढ़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने विश्वसनीय और सटीक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ द्वारा एकत्र किए गए विश्वसनीय डेटा से विकास, योजना और नीति निर्माण में मदद मिलेगी।

एनआईए माता मनसा देवी मंदिर में लगाएगा 9 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर

पंचकूला। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकूला की ओर से चैत्र नवरात्र के पावन उपलक्ष्य में माता मनसा देवी मंदिर परिसर में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित लगाया जाएगा। यह स्वास्थ्य जांच शिविर 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें हर रोज नवरात्र मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उप चिकित्सा अधीक्षक (डीएमएस) डॉ. गौरव गर्ग ने बताया कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा और डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 से चैत्र एवं शारदीय नवरात्री के पावन अवसर पर शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकों की टीम तैनात रहेगी, जो श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच करेगी और जरूरतमंद लोगों को निशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। स्वास्थ्य शिविर का समन्वयक डॉ. अनुराग कुशल और डॉ. मानसी ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है, जिनकी देखरेख में शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान भीड़ और मौसम में बदलाव के कारण अक्सर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, ऐसे में यह शिविर उनके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य परामर्श मिलेगा, साथ ही उनमें आयुर्वेद के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

राजकीय महाविद्यालय कालका में आज रक्तदान शिविर का आयोजन

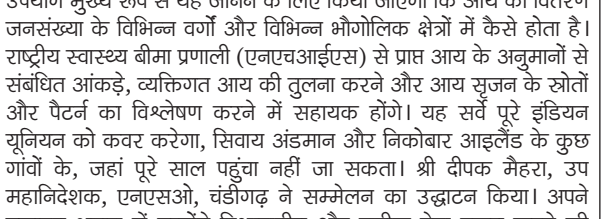

पंचकूला/कालका। राजकीय महाविद्यालय कालका में कल 18 मार्च को प्रातः 10:00 बजे से 3:00 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन युवा रेड क्रॉस सोसायटी और श्री शिव कावड़ महासंघ के संयोजन से किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा युवाओं में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम एवं प्रशिक्षित स्टाफ की देखरेख में रक्तदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर गीता सुखीजा ने सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस पुनीत कार्य में योगदान देने का आह्वान किया।

मनीमाजरा बाजार की बदहाली पर दुकानदारों का फूटा गुस्सा, प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग

मनीमाजरा। मनीमाजरा मुख्य बाजार की जर्जर सड़कों, लटके हुए बिजली के तारों और जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर स्थानीय दुकानदारों और समाजसेवियों ने कड़ा रोष जताया। प्रदीप कुमार गौतम (ज्योतिषी) के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध में बाजार की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए संबंधित विभागों से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने बताया कि बाजार में बिजली के नंगे और लटके हुए तार किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। वहीं, टूटी-फूटी सड़कों के कारण ग्राहकों की आवाजाही में भारी कमी आई है, जिससे व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके अलावा, हल्की बारिश में भी जलभराव की समस्या के चलते दुकानदारों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

साइबर सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक ने एसडी कॉलेज में किया कार्यक्रम

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सेक्टर-32 स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की ओर से गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सेक्टर-32 में डिजिटल सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों के प्रति सचेत करना और व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना था। इस दौरान ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नवनीत कौर ने डिजिटल सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर अत्यंत सहज और प्रभावी ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार, साइबर धोखाधड़ी से बचाव, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार उपयोग और ऑनलाइन बैंकिंग लेन-देन के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने व्याख्यान में उन्होंने दैनिक जीवन से जुड़े व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से साइबर अपराधों के सामान्य तरीकों को स्पष्ट किया और उनसे बचने के सरल व प्रभावी उपाय बताए। विशेष रूप से उन्होंने अनजान लिंक, संदिग्ध कॉल्स और भ्रामक संदेशों से सतर्क रहने, मजबूत पासवर्ड का उपयोग और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-32 शाखा के शाखा प्रबंधक विष्णु अग्रवाल भी उपस्थित रहे। डॉ. अजय शर्मा ने बैंक द्वारा डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए इस कदम की सराहना की और कहा कि आज के तकनीक-प्रधान युग में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार अपनाना अत्यंत आवश्यक है। वहीं, विष्णु अग्रवाल ने भी कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए और विद्यार्थियों तथा व्यापक समाज में वित्तीय साक्षरता और साइबर जागरूकता बढ़ाने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने प्रतिभागियों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते समय सतर्क रहने और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। सत्र का समापन एक इंटरैक्टिव चर्चा के साथ हुआ, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल लेन-देन से जुड़े अपने सवालों के समाधान के लिए वक्ता से सीधे संवाद किया।

यह कार्यक्रम न केवल ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल सतर्कता और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के महत्व को भी रेखांकित किया।

नगर निगम आयुक्त विनय कुमार के नेतृत्व पंचकूला में प्रातः कालीन निरीक्षण जारी

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

- सिविल अस्पताल के पास कचरा स्थल हटाया, नगर निगम की त्वरित कार्रवाई का उदाहरण

पंचकूला नगर निगम के आयुक्त श्री विनय कुमार के नेतृत्व में प्रातः कालीन निरीक्षण अभियान से पूरे शहर में स्वच्छता और नागरिक प्रबंधन को मजबूती मिल रही है। छठे दिन, आयुक्त ने नगर निगम की टीम के साथ सेक्टर-6 का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में घर-घर कचरा संग्रहण, पार्कों का रखरखाव, अतिक्रमण संबंधी मुद्दे और सार्वजनिक शौचालयों की देखरेख जैसे महत्वपूर्ण नागरिक पहलुओं की समीक्षा की गई। निवासियों की शिकायतों को मौके पर सुना गया और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निवारण के निर्देश जारी किए गए। इस दौरान मेशान फाउंडेशन के बच्चों ने कचरा पृथक्करण और प्लास्टिक उपयोग कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया । उनके द्वारा दी गई एक आकर्षक प्रस्तुति को खूब सराहा गया। सातवें दिन, सेक्टर-6 में निरीक्षण जारी रहा। इसमें सड़क सफाई, चल रहे सिविल कार्य, अतिक्रमण की स्थिति और पार्कों के रखरखाव की गहन समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि टोपियरी पार्क के पास सिविल अस्पताल के कोने पर स्थित कचरे के जमाव वाले स्थल को हटाना रही, जो जमीनी स्तर पर तत्काल कार्रवाई के प्रति नगर निगम की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

आयुक्त ने दोहराया कि इन निरीक्षणों का उद्देश्य लगातार निगरानी, क्षेत्रीय कर्मचारियों की जवाबदेही और स्वच्छता मानकों में सुधार सुनिश्चित करना है। साथ ही, उन्होंने निवासियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पंचकूला को स्वच्छ, हरा-भरा और सुव्यवस्थित रखने का संदेश दिया।

सीसीए पंजाब टेलीकॉम सर्किल, चंडीगढ़ द्वारा जालंधर में त्रैमासिक पेंशन अदालत एवं जीवन प्रमाण-पत्र संग्रह शिविर का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/जालंधर

संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत नियंत्रक संचार लेखा (उउअ) कार्यालय, पंजाब टेलीकॉम सर्किल, चंडीगढ़ द्वारा 17 मार्च 2026 को जालंधर में दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए त्रैमासिक पेंशन अदालत एवं जीवन प्रमाण-पत्र संग्रह शिविर के साथ एक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। श्री अक्षय गुप्ता, उप नियंत्रक संचार लेखा, पंजाब ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर पेंशन स्वीकृति तथा पेंशन वितरण से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई।

पेंशन अदालत के दौरान, सुश्री हरदीप कौर, लेखा अधिकारी ने अध्यक्ष श्री अक्षय गुप्ता को अवगत कराया कि कार्यालय को कुल 9 पेंशन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 9 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। अपने मुख्य संबोधन में, श्री अक्षय गुप्ता, उप नियंत्रक संचार लेखा, पंजाब ने कहा कि उनका कार्यालय भारत सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को कुशल एवं समयबद्ध विभागीय पेंशन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि त्रैमासिक पेंशन अदालत के अतिरिक्त, कार्यालय पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

अध्यक्ष ने बताया कि कार्यालय द्वारा ऐसे काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां पेंशनर अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं, पेंशनर पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा मोबाइल नंबर और पते के अद्यतन के लिए आवेदन दे सकते हैं ताकि उन्हें पेंशन अभिलेखों में अद्यतन किया जा सके। श्री अक्षय गुप्ता ने जोर देकर कहा कि जहां कार्यालय पेंशनरों को प्रभावी सेवाएं प्रदान कर रहा है, वहीं सेवाओं में और सुधार के लिए उनके सुझावों का भी स्वागत करता है। पेंशनरों को अपने बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पेंशनरों के लाभ के लिए भारत सरकार के डिजी लॉकर पर जागरूकता वीडियो, उमंग एप्लिकेशन पर जागरूकता वीडियो. साइबर जागरूकता एवं डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव पर व्याख्यान, वरिष्ठ सलाहकार (नेत्र रोग विशेषज्ञ) द्वारा स्वास्थ्य वार्ता, डॉक्टर (डायटीशियन) द्वारा स्वास्थ्य वार्ता, दैनिक जीवन में योग अभ्यास पर व्याख्यान, जीवन प्रमाण-पत्रों का संग्रह, नो योर पेंशनर प्रपत्रों और पहचान पत्र आवेदनों का संग्रह, प्रतिभागियों को पौधों के पौधों (पौधारोपण हेतु पौधे) का वितरण और पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। शिविर की मुख्य विशेषता उप नियंत्रक संचार लेखा, श्री अक्षय गुप्ता के साथ एक-से-एक संवादात्मक सत्र रहा, जिसमें पेंशनरों को अपनी समस्याओं और सुझावों पर सीधे चर्चा करने का अवसर मिला। त्रैमासिक पेंशन अदालत और कल्याण शिविर को पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अत्यंत सराहा गया। आभार और प्रशंसा व्यक्त करते हुए, पेंशनर्स एसोसिएशन, जालंधर के अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह ने कहा कि एसोसिएशन और जालंधर जिले के पेंशनर उउअ कार्यालय द्वारा प्रदान की जा रही त्वरित सेवाओं से संतुष्ट हैं। सत्र का समापन करते हुए, श्री अक्षय गुप्ता, उप नियंत्रक संचार लेखा, पंजाब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कार्यालय पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है तथा पेंशन संबंधी सेवाओं को पेंशनरों के घर-द्वार तक पहुंचाने के लिए विभिन्न पहलें कर रहा है।